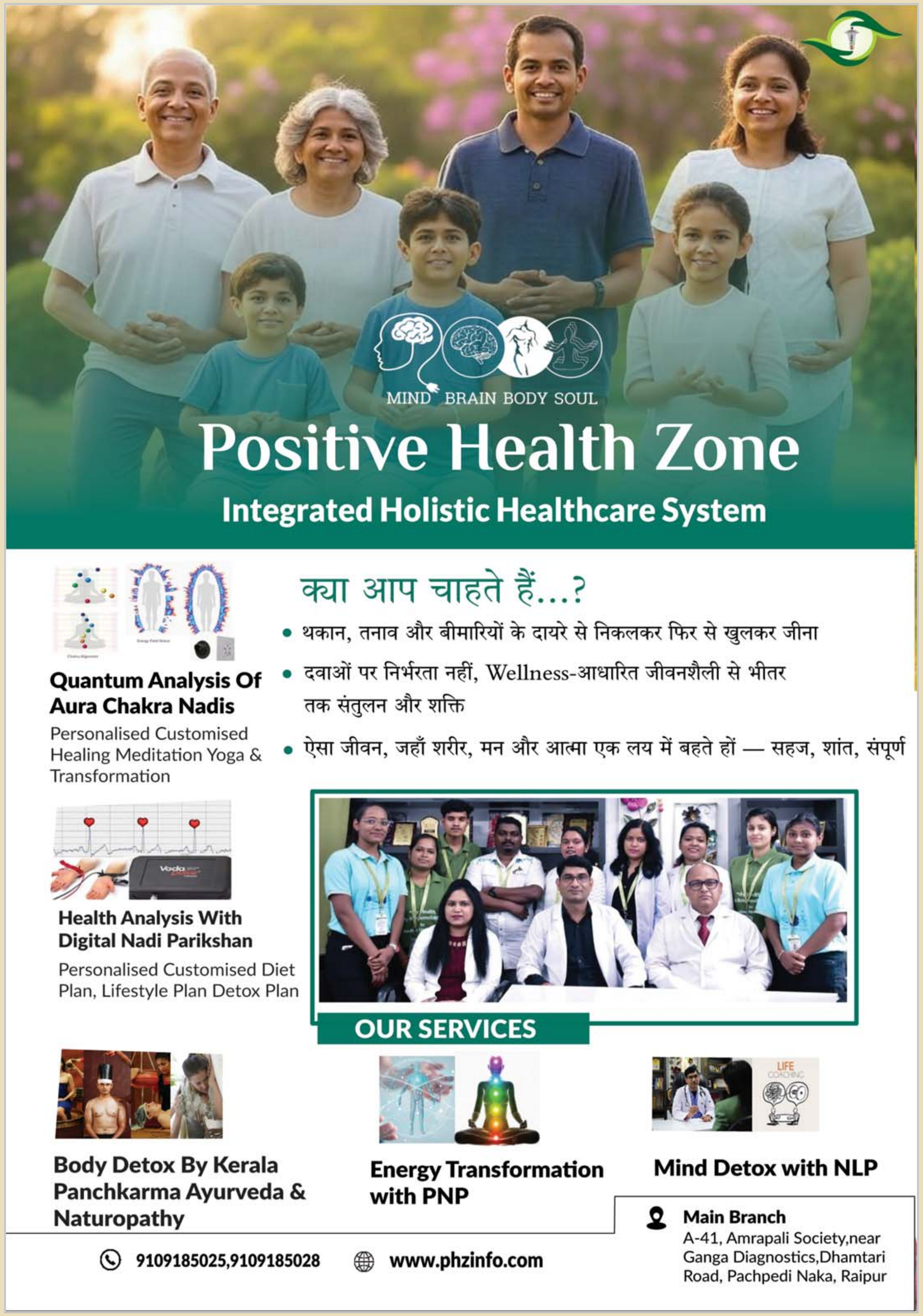

रणनीति बनाम रणनीति

फॉरेस्ट से फार्मेसी तक

संघ–भाजपा में नेतृत्व का सूर्योदय या सूर्यास्त?

हरेली: लोक परंपरा में वेलनेस की जीवित प्रयोगशाला

लाईफ वर्सिटी

वर्ष- 03 अंक -02 जुलाई 2025 मूल्य - 35 रु.

www.scgnews.in

सत्ता का 'सर्जिकल एग्जिट'

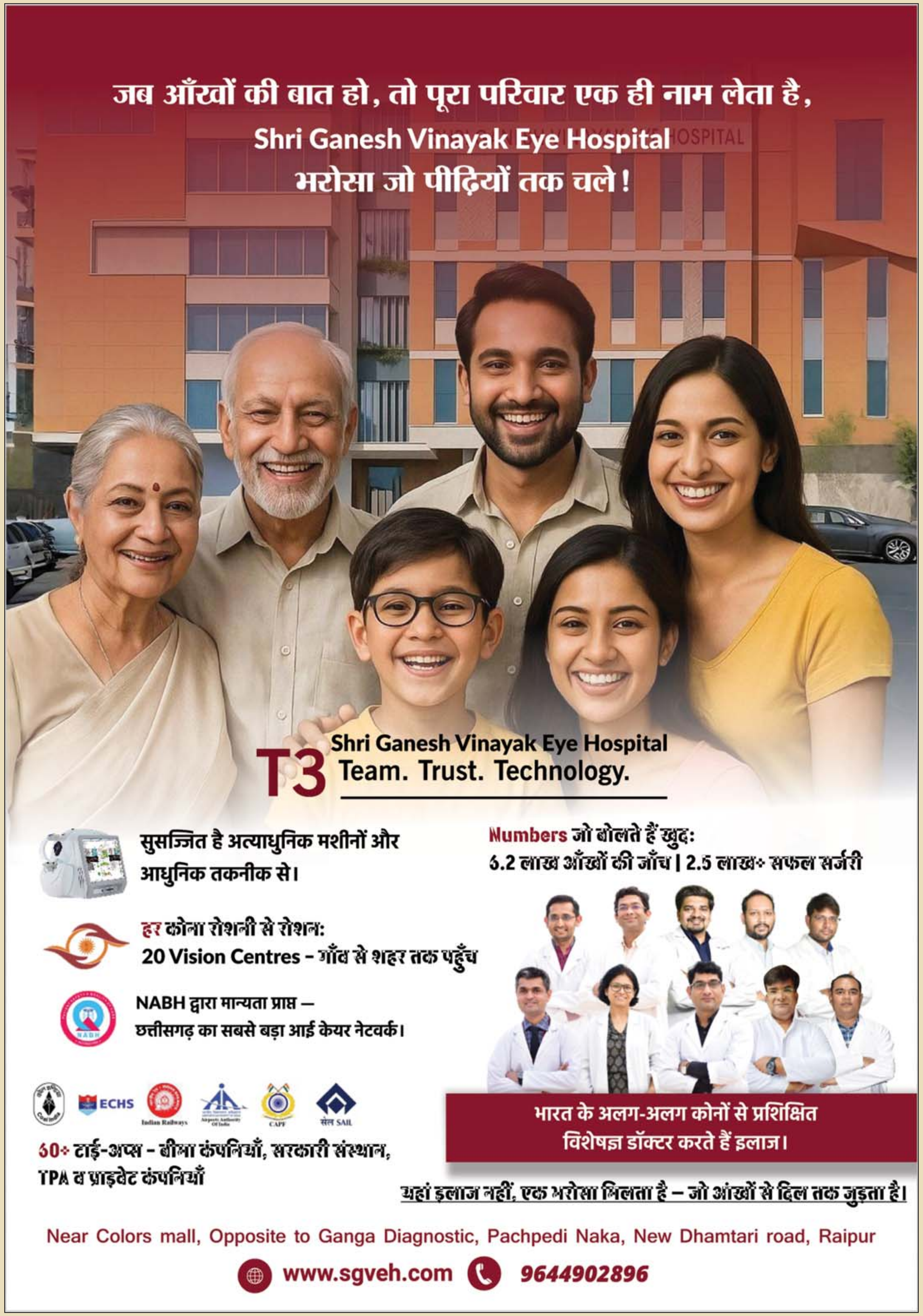
जब आँखों की बात हो, तो पूरा परिवार एक ही नाम लेता है,
Shri Ganesh Vinayak Eye Hospital
भरोसा जो पीढ़ियों तक चले!
Shri Ganesh Vinayak Eye Hospital
T3 Team. Trust. Technology.
सुसज्जित है अत्याधुनिक मशीनों और आधुनिक तकनीक से।
Numbers जो बोलते हैं खुद:
6.2 लाख आँखों की जाँच | 2.5 लाख+ सफल सर्जरी
हर कोना रोशनी से रोशन:
20 Vision Centres – गाँव से शहर तक पहुँच
NABH द्वारा मान्यता प्राप्त –
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आई केयर नेटवर्क।
ECHS
भारत के अलग-अलग कोनों से प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर करते हैं इलाज।
60+ टाई-अप्स – बीमा कंपनियाँ, सरकारी संस्थान,
TPA व प्राइवेट कंपनियाँ
यहां इलाज नहीं, एक भरोसा मिलता है – जो आंखों से दिल तक जुड़ता है।
Near Colors mall, Opposite to Ganga Diagnostic, Pachpedi Naka, New Dhamtari road, Raipur
www.sgveh.com 9644902896

बदलते
बस्तर
की नई तस्वीर
327 गांवों में
नियद नेल्ला नार योजना से तीव्र विकास
350 स्कूलों
में दोबारा शुरू हुई पढ़ाई
278 किलोमीटर
नई सड़कों का निर्माण
11 वृहद
पुलों का निर्माण
140 किलोमीटर
नई रेल लाइन विस्तार की स्वीकृति
1000 नए
मोबाइल टावरों की स्थापना
5,500 से
अधिक घरों का विद्युतीकरण
40,000 से
अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत रोजगार अवसर
3202 नए
बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन
5,500 प्रति
मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता का भुगतान
संवाद- 13342/104
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
सुशासन से समृद्धि की ओर
Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

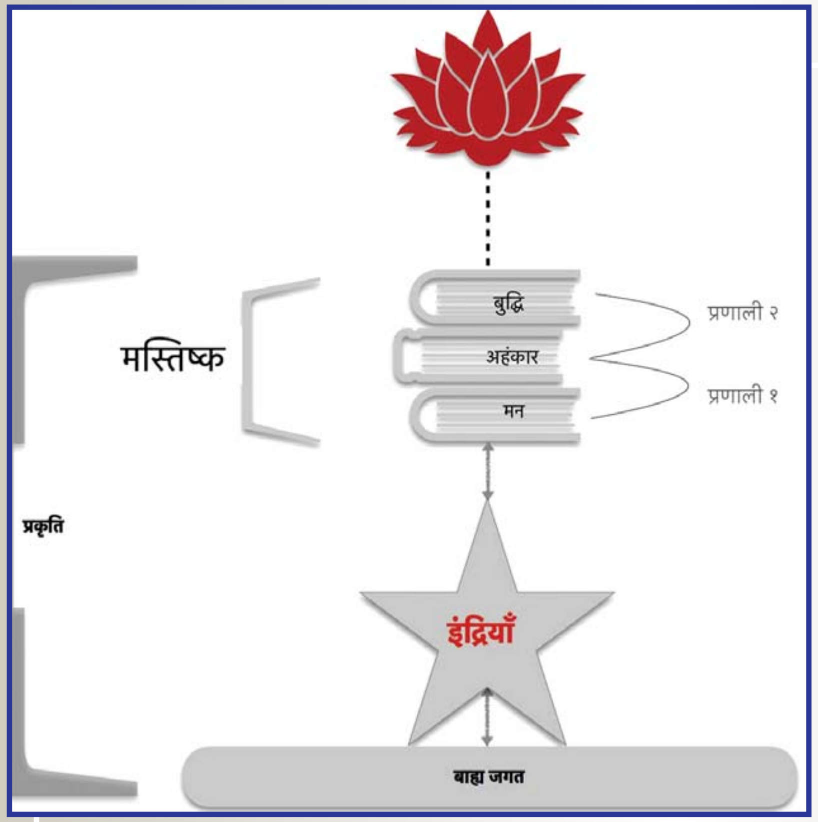

दृष्टा बनें, दृश्य नहीं

नरेन्द्र पाण्डेय

हम अपने-आप से एक सवाल पूछें—क्या हम देख रहे हैं, या फँसे हुए हैं?

सांख्य कहता है—यह ब्रह्मांड दो तत्वों से बना है- प्रकृति और पुरुष।

प्रकृति – जो बदलती है।

पुरुष – जो बस देखता है।

सवाल ये नहीं कि प्रकृति क्या कर रही है। सवाल यह है कि पुरुष कहाँ देखना छोड़ देता है और जुड़ जाना शुरू कर देता है।

प्रकृति की आदत है दोहराव की।

हर साल वसंत आता है, हर रात एक सवेरा लाती है।

हम भी वही हैं – वही मोह, वही क्रोध, वही चिंता, वही तृष्णा।

हम बदलते नहीं, हम घूमते हैं – एक ही वृत्त में, बार-बार।

अब रुकिए।

एक क्षण रुकिए और पूछिए- क्या आत्मा भी इस वृत्त का हिस्सा है?

उत्तर आसान नहीं है। लेकिन गहराई में उतरिए, तो उत्तर चीखता है – 'नहीं!'

आत्मा इस नाटक की दर्शक है, पात्र नहीं।

वह है साक्षी – जो बस देखती है, टोकती नहीं, टकराती नहीं।

लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है।

जब यह आत्मा कहती है–'यह मेरा शरीर है',

जब यह मन के रोने पर कहती है–'मैं दुखी हूँ',

जब यह इंद्रियों की लोलुपता को 'अपनी इच्छा' मान लेती है,

तो वह प्रकृति के जाल में फँस जाती है।

और तब शुरू होता है एक चक्र – न केवल पुनर्जन्म का,

बल्कि मनःस्थिति के प्रत्यावर्तन का।

हमारा जीवन फिर एक थियेटर बन जाता है जहाँ हर दृश्य दोहराया जाता है-

वही मोहब्बत, वही जुदाई।

वही सपना, वही टूटन।

वही इच्छा, वही थकावट।

हम बदलते नहीं, बस रिपीट मोड पर जीते हैं।

यह वही जगह है जहाँ सांख्य दर्शन हमें झकझोरता है।

कहता है- 'तू वह नहीं है जो दुःखी है।

तू वह है जो दुःख को देख रहा है।

तू दृश्य नहीं है, तू दृष्टा है।'

लेकिन दृष्टा होने के लिए साहस चाहिए।

अपना दुःख देखना आसान है, उससे असंग होना कठिन।

अपने सुख से विमुख होना, अपने गौरव से परे होना यह सब एक क्रांति है, जो भीतर घटती है।

यही है सांख्य की पुकार – 'जागो!'

देखो, पर जुड़ो मत।

रहो, पर बहो मत।

जियो, पर जकड़ो मत।

आत्मा मुक्त है, लेकिन वह तब तक बँधी है जब तक वह स्वयं को पहचानती नहीं।

वह न अभिनेता है, न संवाद लेखक –

वह बस एक देखती हुई चेतना है, जो इस नाटक से ऊपर है।

और जब वह यह पहचान लेती है, तब न तो जन्म रहता है, न मरण –

बस एक साक्षी भाव रह जाता है, जो पूर्ण है, शांत है, और मुक्त है।

हरेली, हर्बल और हाईपोलिटिक्स

नरेन्द्र कुमार पाण्डेय
सम्पादक

जब मिट्टी की महक और सत्ता की चालें एक साथ बदलें, तो समझिए कोई राज्य केवल नक्शे पर नहीं, आत्मा में भी आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ आज इसी मोड़ पर खड़ा है – जहाँ पर्व परंपरा बन रहे हैं और परंपरा प्रतिरोध। जहाँ राजनीति चुप है, और चुप्पी खुद भाषा बन चुकी है।

श्रावण की अमावस्या आई... और छत्तीसगढ़ मुस्कुरा उठा। लेकिन इस बार हरेली तिहार केवल हल की पूजा या गेड़ी का रोमांच नहीं था। यह एक सांस्कृतिक प्रतिरोध था – उजड़ते जंगलों के विरुद्ध, एक हरित क्रांति का एलान।

सरकार ने 'हर्बल मिशन' और 'औषधीय वनों' की बात की, तो गांव के बच्चे तुलसी और नीम की टहनी लगाकर बता गए कि 'ग्रीन इकोनॉमी' का पाठ उनके डीएनए में पहले से लिखा हुआ है। अब हरेली कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि हर्बल इकोनॉमिक्स की grassroots movement बन रही है। लेकिन सवाल यही है – क्या दिल्ली तक ये हरियाली पहुँचेगी?

दिल्ली की सत्ता में अलक्षित शब्दों का मौसम है। प्रधानमंत्री का मौन और संघ प्रमुख की 'अभ्यंतर व्यथा' – दोनों मिलकर भाजपा की आत्मा को आईना दिखा रहे हैं। 2024 में '400 पार' की गर्जना अब जनादेश की जटिलता में बदल चुकी है। क्या ये संघ के लिए Post-Modi Era का संकेत है? या फिर भाजपा भीतर से नेतृत्व पुनर्गठन की ओर बढ़ रही है? मोदी-शाह-नड्डा ट्रायो के आगे अब एक नया वैचारिक केंद्र उभरने की आहट है – जो शायद 2029 की स्क्रिप्ट आज ही लिख रहा हो।

उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने संविधान प्रेमियों को चौंका दिया। बीमारी की बात कही गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह स्वास्थ्य से ज्यादा सत्ता का मामला नजर आ रहा है। क्या यह एक सर्जिकल एक्सिट है? क्या धनखड़ बंगाल या राजस्थान में किसी विशेष मिशन के लिए निकल रहे हैं? अगर हरेली छत्तीसगढ़ का स्वस्थ प्रतिरोध है, तो धनखड़ का इस्तीफा केंद्र की संवैधानिक बेचैनी का लक्षण।

इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने State Capital Region (SCR) की घोषणा। रायपुर, अटल नगर, भिलाई, दुर्ग – अब केवल भौगोलिक नाम नहीं, बल्कि एक सामूहिक राजनीतिक चेतना का नक्शा बनने जा रहे हैं। यह निर्णय छत्तीसगढ़ को एक 'उभरते राज्य' से 'संगठित शक्ति' में बदल सकता है, अगर इसका शहरीकरण 'शुद्धिकरण' की शैली में किया जाए। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता की राष्ट्रीय दौड़ में बाज़ी मार ली। जब बस्तर जैसे ज़िले शौचालयों से लेकर कचरा प्रबंधन तक में मॉडल बन जाएँ, तो समझिए राज्य ने केवल स्कोर नहीं – सामाजिक चेतना का स्तर ऊँचा किया है।

इस सबके बीच एक प्रश्न बचा है - क्या छत्तीसगढ़ अपने ही भीतर एक नई राष्ट्रीय पहचान गढ़ रहा है? या फिर वह भी उन्हीं चक्रों में फँसने वाला है, जो दिल्ली तय करती है? क्योंकि जब रायपुर की गंध दिल्ली तक जाती है, तब देश की राजनीति भी तुलसी की गंध महसूस करती है। लेकिन भारत की राजनीति में, आज जो दिखता है, वह होता नहीं – और जो होता है, वह कभी दिखता नहीं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा आसमां पब्लिशर्स इंडिया प्रा.लि. जयराम काम्पलेक्स गली, मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुर, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979
E-mail : scgnewsraipur@gmail.com | www.scgnews.in

अंदर के पृष्ठों पर

1.सत्ता का 'सर्जिकल एग्जिट' 2
2.रणनीति बनाम रणनीति 5
3.कांग्रेस की चुप्पी और भूपेश.. 7
4.संघ–भाजपा में नेतृत्व... 9
5.बस्तर से ब्रसेल्स तक.... 12
6.छत्तीसगढ़ की हर्बल क्रांति 13
7.42000 सपनों की धज्जियां...16
8.बस्तर में फैल रहा है.... 19
9.बिखेरी स्वच्छता की चमक..... 21
10हरेलीः लोक परंपरा में 22
11. दृष्टा बनें, दृश्य नहीं 24

SCAN & PAY
UPI ID: 329944413263914@cnrb

लाईफ वर्सिटी के प्रचार–प्रसार में सहयोग करें।

परामर्श मण्डल
■ डॉ. शुभ्रा सान्याल (नई दिल्ली)
■ डॉ. अनिल गुप्ता (रायपुर)

परिकल्पना
रजनी कान्त पाण्डेय
भूषण

बीमारी का बहाना या सत्ता का 'सर्जिकल एग्जिट'?

'सवाल यह नहीं है कि इस्तीफा दिया गया-सवाल यह है कि इस्तीफा कब, कैसे और क्यों दिया गया?'

'जब जवाब संसद से गायब हो, तब सवाल सड़क पर उतरते हैं' भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 21 जुलाई 2025 की तारीख एक सामान्य सोमवार की तरह दर्ज नहीं की जाएगी। यह दिन उस पन्ने की तरह है जिसे अचानक पलटा गया — लेकिन उस पन्ने के पीछे की इबारत अब भी अधूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, बिना किसी आधिकारिक पुष्टि, बिना किसी चिकित्सा बुलेटिन, बिना किसी प्रेस ब्रीफिंग के — अपने आप में एक गूढ़ राजनीतिक घटना बन चुका है। 'सवाल यह नहीं है कि इस्तीफा दिया गया-सवाल यह है कि इस्तीफा कब, कैसे और क्यों दिया गया?'

संविधान कहता है, लेकिन राजनीति क्या कहती है?

भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक माना गया है। उनका काम केवल राज्यसभा की अध्यक्षता तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संविधानिक पदभार को निभाना भी होता है। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई उपराष्ट्रपति यूं अचानक 'बीमार' हो जाए और त्यागपत्र भेज दे — वह भी तब, जब संसद का मानसून सत्र चल रहा हो, और वह खुद दिन भर सदन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हों।

स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वाले वे पहले उपराष्ट्रपति बन गए — यह खबर खुद उपराष्ट्रपति के ऑफिसियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रसारित की गई, लेकिन हैरानी की बात यह कि इस पर न राष्ट्रपति भवन से कोई बयान आया, न प्रधानमंत्री कार्यालय से, न गृह मंत्री और न स्वास्थ्य मंत्रालय से। आखिरकार यह देश के संवैधानिक व्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी की बात थी — कोई कॉर्पोरेट इस्तीफा नहीं।

21 जुलाई- सिर्फ मानसून सत्र नहीं, 'महाभियोग' का दिन भी था।

अब ज़रा घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं

सुबह 11.00 बजे-उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही चला रहे थे। पूरे जोश में। बिना किसी थकावट या स्वास्थ्य समस्या के संकेत।

21 जुलाई 2025, दोपहर 2 बजे- राज्यसभा में विपक्ष के 145 सांसद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर एक नोटिस प्रस्तुत करते हैं। सत्ता और विपक्ष — दोनों के सांसद दस्तखत करते हैं। यह एक सामूहिक असहमति थी, भारत की न्यायपालिका को लेकर एक नया अध्याय खुल रहा था।

21 जुलाई 2025, शाम 4 बजे- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, न सिर्फ इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं बल्कि चर्चा की अनुमति देते हैं और संयुक्त समिति के गठन की बात भी करते हैं। सदन चल रहा था, लेकिन असल में सियासत दौड़ रही थी।

21 जुलाई 2025, शाम 6.30 बजे- कैबिनेट मंत्रियों के बीच बंद कमरे की बैठकें होती हैं। विशेष रूप से राजनाथ सिंह के ऑफिस में हलचल होती है। 20-25 मिनट तक सत्ता के केंद्र में कुछ ऐसा होता है — जिसकी तस्वीरें नहीं, पर साज़िशें ज़रूर छनकर बाहर आती हैं।

21 जुलाई 2025, रात 9 बजे- धनखड़ जी 'अस्वस्थ' हो जाते हैं। एक पत्र राष्ट्रपति को भेजते हैं — स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा। लेकिन हैरानी की बात ये कि इस पत्र पर न तो प्रधानमंत्री, न गृहमंत्री, न स्वास्थ्य मंत्री और न ही स्वयं राष्ट्रपति की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया आती है।

बीमारी' की पटकथा में छिपा 'बॉडी लैंग्वेज' का सच

यह कहानी उस राजनीतिक एपीसोड की है जहाँ संवैधानिक पदधारियों का इस्तीफा अब लोकतंत्र के 'सीन प्ले' में एक स्क्रिप्टेड एग्ज़िट जैसा महसूस होने लगा है। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति न केवल सदन में सक्रिय थे,

हरेली डीटॉक्स उत्सव- जहां पर्व बन गया चिकित्सा

'लाईफ वार्सिटी' और 'पाज़िटिव हेल्थ ज़ोन' के सौजन्य से श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित हरेली डीटॉक्स उत्सव ने इस पर्व को चिकित्सा और चेतना की नई परिभाषा दी।

जब मौसम हो गुरु और योग हो संवाद

छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा कहते हैं - हरेली केवल त्योहार नहीं, ये चिकित्सा है। ऋतु और योग के संदर्भ में, यह वह अध्याय है जहाँ प्रकृति खुद गुरु बन जाती है। जब पंचमहाभूत संतुलन में होते हैं, तब यह संतुलन शरीर, मन और प्राण के लिए अमृत समान होता है। योग इसी संतुलन की साधना है। यही कारण है कि इस समय व्रत, संकल्प, औषध प्रयोग और खेती जैसे कर्म भी अधिक प्रभावकारी माने जाते हैं। हरेली, वस्तुतः शरीर और प्रकृति के बीच उस मौन संवाद का उत्सव है, जहाँ ऋतु 'ऋषि' हो जाती है और वर्षा की फुहारें 'उपदेश'।

न्यूरो-फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर माइंडफुलनेस तक

डॉ. अनिल गुप्ता ने जब गेड़ी चढ़ने को 'न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की टेस्टिंग' कहा — तब यह स्पष्ट हुआ कि हमारी लोक परंपराएं केवल सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि कॉग्निटिव साइंस और बॉडी-ब्रेन कोऑर्डिनेशन की जीवंत प्रयोगशालाएं हैं। बचपन में गेड़ी पर चढ़ना — न केवल संतुलन साधने की कला थी, बल्कि proprioception (body awareness), motor control, और risk anticipation जैसे न्यूरोलॉजिकल responses को सक्रिय करने का अभ्यास भी था। हरेली जैसे त्योहारों में शरीर, मस्तिष्क और प्रकृति के बीच का यह संवाद, आधुनिक न्यूरोसाइंस की भाषा में 'एंबॉडीड इंटेलिजेंस' (Embodied Intelligence) कहलाता है — जो आज की दुनिया में लाखों डॉलर की थेरेपीज़ और ब्रेन ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का हिस्सा है। लेकिन हमारे गांवों में यह सहजता से होता था, उत्सव की मुस्कान के साथ।

छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोकचिंतक उदय भान सिंह चौहान इसे 'लोक-आयुर्वेद की जीवित प्रयोगशाला' कहते हैं — जहाँ मिट्टी की सोंधी गंध संक्रमण से लड़ती है, नीम की कड़वाहट मानसिक विष को हरती है, और गाँव के सामूहिक उल्लास में 'सामुदायिक चेतना' पुनर्जीवित होती है। यह पर्व बताता है कि जब मौसम की नमी बढ़ती है, तब शरीर को शुद्धता, मन को स्थिरता और समाज को सामूहिक एकता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है — और हरेली चुपचाप, बिना किसी प्रचार के, यह सबकुछ करती है।

हरेली और नैचुरोपैथी- जब खाना, खेल और ध्यान एक हो जाए

कार्यक्रम की शुरुआत नीम जल के छिड़काव और चंदन अभिषेक से हुई। प्रातःकालीन योग-प्राणायाम और ध्यान सत्र के बाद सभी को गुड़-तुलसी का डीटॉक्स ड्रिंक प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ी परिधान में बच्चियों द्वारा राज गीत और भरथरी शिव भजन ने वातावरण को भक्ति और सौंदर्य से भर दिया।

पाज़िटिव हेल्थ ज़ोन की नैचुरोपैथी टीम द्वारा ऋतु-विशेष सुपाच्य भोजन परोसा गया — जो स्वास्थ्य के साथ स्वाद का भी ध्यान रखता था। शाम को चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, और अंत में भारती बंधु की टोली द्वारा भजन संध्या ने कार्यक्रम का समापन लोक उल्लास और आत्मिक आनंद में बदल दिया।

हरेली जीवन का रीसेट बटन

लाईफ वार्सिटी के सम्पादक नरेंद्र पाण्डेय के शब्दों में — हरेली केवल एक पर्व नहीं। यह एक इनर बॉडी-रिट्रीट है, एक ऐसा रीसेट बटन जो शरीर और मन को वर्षा ऋतु के साथ समन्वय में पुनः सक्रिय करता है। जहाँ भोजन, व्यवहार, खेल और ध्यान — सब कुछ संस्कारमय चिकित्सा बन जाता है। आज जब वेलनेस शब्द अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है, छत्तीसगढ़ के गाँव उस वेलनेस को वर्षों से लोक परंपरा के रूप में जीते आ रहे हैं — बिना किसी ब्रांडिंग, बिना किसी विज्ञापन के।

हरेली

लोक परंपरा में वेलनेस की जीवित प्रयोगशाला

> **हरेली मतलब प्रकृति के चारों तरफ हरियाली से है। किसान खेत में जुताई-बोआई, रोपाई, बियासी के कार्य पूर्ण करके इस त्यौहार को मनाता है। हरेली मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है, जो ज़मीन और जीवन को सहारा देने वाले औज़ारों के प्रति कृतज्ञता की भावना को उजागर करता है।**

श्रावण की अमावस्या — जब बादलों की फुहारें धरती की प्यास बुझाती हैं, तब छत्तीसगढ़ मुस्कुराता है। हरियाली की ओढ़नी पहनकर, हल-बैल, किसान, खेत, नीम और तुलसी - सब कुछ जैसे नए प्राण पा लेते हैं। यही क्षण है — हरेली तिहार का।

पर ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक संवेदना है — जो परंपरा, प्रकृति और प्रगति के त्रिवेणी संगम में नहाई हुई है।

मुख्यमंत्री निवास मे परंपरा और तकनीक का समागम

इस वर्ष छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा तब पूरी गरिमा से प्रकट हुई जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निवास में हरेली तिहार का आयोजन हुआ। यह आयोजन महज़ उत्सव नहीं था, बल्कि एक जीवंत प्रदर्शन था — जिसमें मिट्टी की महक से लेकर मशीनों की धड़कन तक, सब एक साथ समाहित थे।

मुख्यमंत्री निवास में सजाई गई प्रदर्शनी किसी चलायमान संग्रहालय से कम नहीं थी। 'काठा' जैसे पारंपरिक मापक, 'झांपी', 'खुमरी', 'तुतारी' से लेकर आधुनिक पावर टिलर और बीज ड्रिल तक — यह दृश्य स्पष्ट करता है कि छत्तीसगढ़ केवल अतीत में जीने वाला राज्य नहीं, बल्कि वह भविष्य के साथ कदमताल करता हुआ सांस्कृतिक योद्धा है।

मुख्यमंत्री साय का वक्तव्य-'परंपरा और तकनीक के समन्वय से छत्तीसगढ़ की खेती और अधिक टिकाऊ बनेगी'- इस बात की उद्घोषणा है कि कृषि क्षेत्र को केवल स्मृति नहीं, रणनीति से जोड़ा जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह का यह कथन कि 'हरेली वह दिन है जब स्वयं शिव-पार्वती किसान के खेतों का निरीक्षण करने आते हैं,' केवल मिथक नहीं है — बल्कि यह संवेदनशील कृषि चेतना की अभिव्यक्ति है।

खेती, पशुधन, हल-बैल, और जल - इन सभी की पूजा प्राकृतिक संतुलन और कृतज्ञता भाव की नींव है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी आज मान्यता दे रहा है।

किसान, वोटर नहीं, विकास भागीदार

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा घोषित योजनाएं — जैसे रू.3100 प्रति क्विंटल की धान खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा — इस दिशा में ठोस संकेत देती हैं कि किसान अब केवल 'वोट बैंक' नहीं, बल्कि विजन बैंक के साझेदार हैं। 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़' की बात हो या किसानों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाना — यह सोच राज्य की स्मार्ट-रूटेड ग्रोथ को परिभाषित करती है।

बल्कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकें ले रहे थे, फ्लोर लीडर्स से संवाद कर रहे थे, और शाम को जयपुर कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। उनके कार्यालय द्वारा 23 जुलाई को जयपुर में होने वाले कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति पहले से जारी की गई थी।

यह सब देखकर सवाल उठता है — क्या किसी को तीन घंटे में ऐसा स्वास्थ्य संकट आ सकता है कि वह देश के इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दे? और अगर ऐसा गंभीर संकट था, तो AIIMS या RML जैसे अस्पतालों में भर्ती क्यों नहीं हुए? मेडिकल बुलेटिन क्यों जारी नहीं किया गया?

यदि उपराष्ट्रपति सच में बीमार थे —

* तो 21 जुलाई को दिनभर की मीटिंग्स, कमेटी की अध्यक्षता, फ्लोर लीडर्स से संवाद और पूरी फुर्ती से राज्यसभा की कार्यवाही क्यों?
* अगर वाकई स्वास्थ्य कारण थे, तो 23 जुलाई को जयपुर में होने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों प्लान किया गया था?
* अगर सच में 'वायरल बुखार' जैसा कुछ था, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोई मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं आया?

और सबसे बड़ा सवाल –

क्या भारतीय लोकतंत्र इतना कमज़ोर है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक ट्वीट भर बनकर रह जाए?

महाभियोग और महा-मौन

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें महाभियोग प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में झांकना होगा।

जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने कुछ मामलों में सत्तापक्ष के हितों को बढ़ावा दिया, विशेषकर कुछ अति-संवेदनशील मीडिया और चुनावी मामलों में। विपक्ष के पास सीधे प्रमाण भले न हों, लेकिन संदेह इतना प्रबल है कि 145 सांसदों ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। और इसी प्रस्ताव को धनखड़ साहब ने स्वीकार किया था।

अब ध्यान दीजिए —

क्या इस महाभियोग प्रस्ताव की स्वीकारोक्ति सत्ता के शीर्ष तंत्र के लिए खतरे की घंटी थी?

क्या इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले ही 'डैमेज कंट्रोल' ऑपरेशन चलाया गया?

कैबिनेट मीटिंग्स- राजनाथ सिंह के दफ्तर में क्या तय हुआ?

21 जुलाई की शाम, जब राजनाथ सिंह के ऑफिस में गहमागहमी दिखी — तब कोई नहीं जानता था कि देश का उपराष्ट्रपति कुछ घंटों में इस्तीफा देने वाला है।

आंतरिक सूत्रों के अनुसार, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के वरिष्ठ अधिकारियों, कुछ ऋस्स पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों और कानूनी सलाहकारों के बीच गंभीर बातचीत हुई।

माना जा रहा है कि चर्चा महाभियोग के प्रभाव, न्यायपालिका की प्रतिक्रियाओं और भविष्य की संवैधानिक जटिलताओं को लेकर थी।

कुछ जानकार इसे 'संवैधानिक विस्फोट से पहले की सर्जरी' बता रहे हैं।

धनखड़ जी की भूमिका – और 'Exit प्लान'?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया ही गया था एक विशेष 'भूमिका' निभाने के लिए।

उन्होंने जजों की नियुक्तियों, कॉलेजियम सिस्टम और न्यायपालिका के फैसलों पर कई बार खुलकर टिप्पणी की।

संसद में कई बार उनकी स्थिति एक 'सिस्टम चैलेंजर' की थी — जो कार्यपालिका के पक्ष में बोलते हुए न्यायपालिका को कठघरे में लाते थे।

कुछ जानकारों के अनुसार, उन्होंने वो भूमिका पूरी कर दी है। अब उनकी ज़रूरत नहीं रही।

तो क्या यह एक पूर्व निर्धारित 'एग्ज़िट स्क्रिप्ट' थी?

क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है?

जब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा इस तरह से होता है —

बिना कैबिनेट मीटिंग की जानकारी के,
बिना राष्ट्रपति की सार्वजनिक स्वीकृति के,
बिना मेडिकल बुलेटिन के,
बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के —

तो यह सिर्फ संवैधानिक शून्यता नहीं, बल्कि जनविश्वास का ह्रास है।

ध्यान रहे, यह वही भारत है जहाँ राष्ट्रपति तक का चयन दलगत राजनीति की धारा से प्रभावित होता है।

अब उपराष्ट्रपति का 'अचानक इस्तीफा' लोकतंत्र के लिए एक 'प्री-प्लांड स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा' जैसा प्रतीत होता है।

कौन-कौन हैं इस नाटकीयता के पात्र?

* **PMO** — पूरी प्रक्रिया की अनदेखी पर चुप क्यों?
* **स्वास्थ्य मंत्रालय** — जब वजह 'सेहत' है तो मेडिकल रिपोर्ट कहाँ?
* **राष्ट्रपति भवन** — क्यों नहीं आया कोई सार्वजनिक संदेश?

✷ **कैबिनेट** — क्या ये सामूहिक चुप्पी साज़िश है?
✷ **न्यायपालिका** — क्या यह महाभियोग की प्रक्रिया को रोकने का दबाव था?

कांग्रेस, AAP और अन्य विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस इस्तीफे को 'रहस्यमयी और चिंताजनक' करार दिया।

AAP नेता संजय सिंह ने इसे 'लोकतंत्र के साथ खिलवाड़' बताया।

टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने कहा — 'देश को सच बताया जाए। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कोई WhatsApp नोटिस नहीं है।'

क्या न्यायपालिका से टकराव की कड़ी थी ये 'एग्ज़िट स्क्रिप्ट'?

✷ जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की चर्चा पहली बार नहीं उठी। लेकिन यह पहली बार था कि राज्यसभा के सभापति ने उसे संविधानिक प्रक्रिया के तहत स्वीकार भी किया और अगली कार्रवाई का संकेत भी दिया।
✷ यह कदम न सिर्फ अभूतपूर्व था, बल्कि सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान की पृष्ठभूमि में संवेदनशील भी था।
✷ ध्यान दें कि यशवंत वर्मा वही जज हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले दिए, जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ माने गए — जैसे-
✷ कुछ मीडिया प्रतिबंधों को असंवैधानिक ठहराना
✷ ईडी/सीबीआई की कार्यवाही में 'बिना जवाबदेही' की आलोचना
✷ विपक्ष के नेताओं के मामलों में निष्पक्षता की मांग

ऐसे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा एक संभावित न्यायिक-राजनीतिक टकराव से बचने की रणनीति भी हो सकता है।

क्या यह 'संवैधानिक क्लाइमेक्स' का पूर्वाभास था?

कुछ जानकार मानते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया यदि आगे बढ़ती, तो यह भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी परिघटना बनती। इससे न्यायपालिका की साख, सरकार की जवाबदेही और लोकतंत्र की बुनियादी संरचना — तीनों सवालों के घेरे में आते।

ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि धनखड़ साहब की भूमिका 'एक निश्चित सीमा तक जाकर' काम करना था — न ज़्यादा, न कम।

और जैसे ही वह सीमा पार होने लगी — 'स्वास्थ्य' एक सांकेतिक वजह बना दी गई। और फिर 'Exit'!

मीडिया की रहस्यमयी चुप्पीः प्रश्न या प्रतिबंध?

इतने बड़े घटनाक्रम पर राष्ट्रीय मीडिया का लगभग मौन रहना, अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। कोई डिबेट नहीं, कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं, और न ही कोई एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हासिल करने की कोशिश।

क्या मीडिया को पहले ही सूचित कर दिया गया था?

या मीडिया इस मुद्दे को संवैधानिक संकट मानकर 'न छेड़ो' जोन में डाल चुकी है?

जो भी हो — जनता को इसका अधिकार है कि उसे जानकारी मिले कि उसके उपराष्ट्रपति ने किस कारण से, किस प्रक्रिया के तहत, और किस डॉक्टर की राय पर इस्तीफा दिया।

जनता के प्रश्न – संसद की चुप्पी

जब जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ नेता इसे 'रहस्यमयी इस्तीफा' कहते हैं, और TMC की सांसद महुआ मोइत्रा इसे 'गोपनीय खेल' करार देती हैं — तो यह बात किसी अफवाह नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत बन जाती है।

कांग्रेस ने पूछा — 'क्या स्वास्थ्य सिर्फ बहाना है?'

बीजेपी खेमे में भी कुछ सांसद इस निर्णय से अचंभित दिखे।

संविधान विशेषज्ञों ने भी कहा-'इस इस्तीफे में 'औपचारिकता' नहीं, सिर्फ 'सूचना' थी।'

तो क्या देश में अब संवैधानिक पदों का भी 'प्लॉट' तैयार होता है?

यह घटना सिर्फ उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की नहीं है। यह एक संकेत है — कि लोकतंत्र के सबसे ऊँचे पदों पर भी अब रणनीति, पटकथा और अभिनय की संभावना है।

✷ क्या उपराष्ट्रपति को क्लाइमैक्स से पहले हटाया गया?
✷ क्या सरकार महाभियोग की प्रक्रिया से बचना चाहती थी?
✷ क्या न्यायपालिका के खिलाफ कार्रवाई से पहले 'संविधानिक सिग्नल' भेजा गया?
✷ या फिर — धनखड़ साहब ने खुद ही 'मंच' छोड़ दिया, जैसे कोई पात्र अपनी भूमिका पूरी करके पर्दे से उतरता है?

धनखड़ साहब के तीन घंटे के घटनाक्रम ने न सिर्फ चेहरा बदला, बल्कि पूरे राजनीतिक 'चैप्टर' को ही बदल दिया है। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, यह एक संवैधानिक सर्जरी थी — बिना एनेस्थेसिया, बिना रिपोर्ट, बिना औपचारिकता।

यह घटना हमें बताती है — भारत में अब संवैधानिक पद भी 'सीज़नल पोस्टिंग' बन रहे हैं। जहाँ कार्यकाल, सेहत से नहीं — सत्ता की स्क्रिप्ट से तय होते हैं। शायद भारत की संवैधानिक राजनीति अब एक बदलाव के दौर में है। जहाँ संविधान का पाठ और राजनीतिक स्क्रिप्ट एक ही मंच पर चलते हैं, लेकिन दोनों के लेखक अलग-अलग होते हैं।

छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय मंच पर बिखेरी स्वच्छता की चमक

केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सात शहरों ने अपनी स्वच्छता की चमक बिखेरी है। बिल्हा नगर पंचायत 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में अब देश का सबसे साफ-सुथरा शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। तीन लाख से दस लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को पूरे देश में दूसरा और 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है।

20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा देश का सबसे स्वच्छ शहर

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में इन तीनों नगरीय निकायों के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के कुल सात नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव, संबंधित निकायों के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी पुरस्कार समारोह में शामिल हुए।

भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर और रायपुर ने भी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार शामिल नई श्रेणी %स्वच्छता सुपर लीग% (एसएसएल) में अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर ने जगह बनाई है। यह सम्मान उन शहरों को दिया गया, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में रहे हैं और वर्तमान वर्ष में शीर्ष 20 शहरों में शामिल हैं। अंबिकापुर ने 50 हजार से तीन लाख जनसंख्या श्रेणी में तथा पाटन और विश्रामपुर ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में एसएसएल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इनके अतिरिक्त, राजधानी रायपुर को छत्तीसगढ़ का प्रॉमिसिंग (Promising) स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने इन शहरों में स्वच्छता के प्रति नागरिकों, स्थानीय निकायों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पुरस्कार राज्य के अन्य शहरों को भी अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने भी आज पुरस्कृत नगरीय निकायों को बधाई दी और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए केवल एक सम्मान ही नहीं, बल्कि स्वच्छता के प्रति निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। आने वाले समय में अन्य नगरीय निकायों को भी स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होंगे। शहरी सरकारों से लेकर राज्य और केंद्र की सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए कई नवाचारों के साथ सतत काम कर रहे हैं।

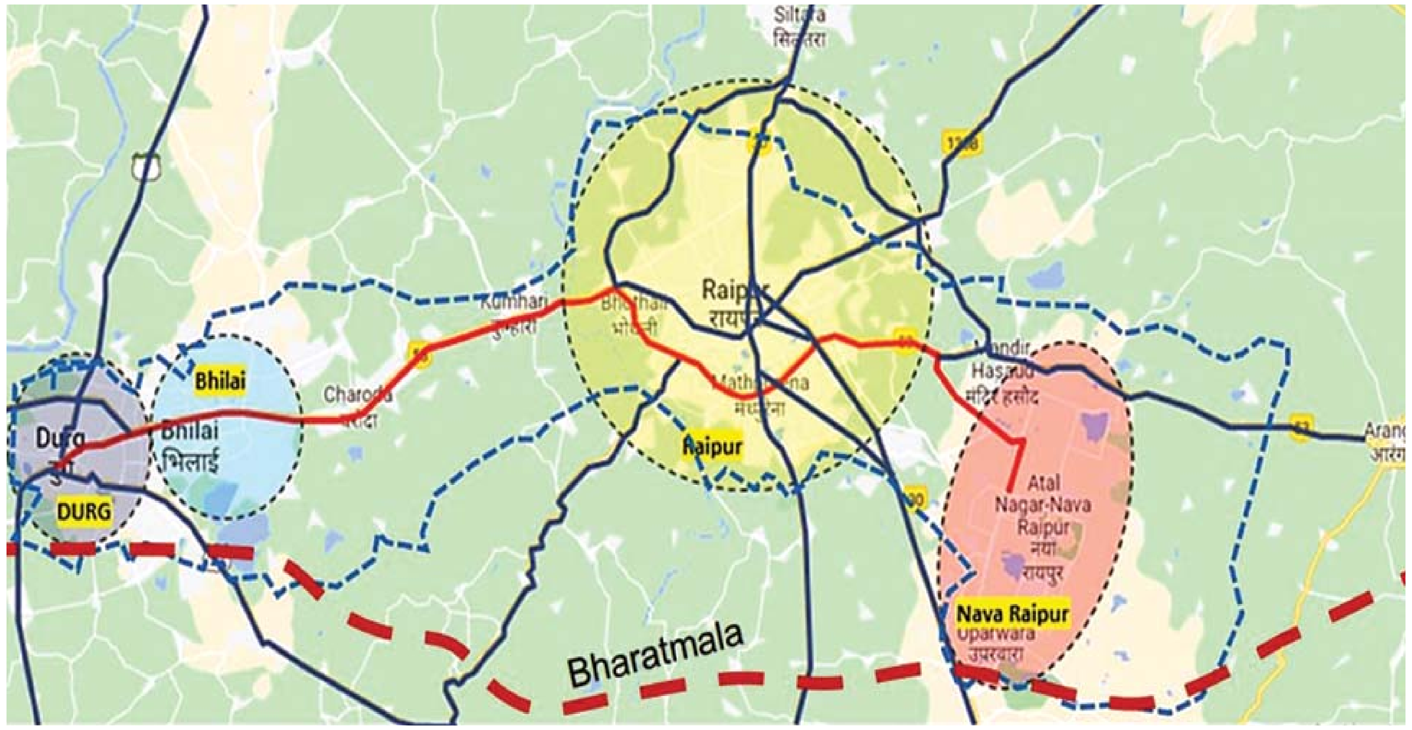

स्टेट कैपिटल रीजन

छत्तीसगढ़ का बनेगा नया ग्रोथ इंजन

राजधानी रायपुर और उसके आस-पास का एरिया, स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के रूप में विकसित होने जा रहा है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ ईंजन बनेगा। विधानसभा में इस संबंध में विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही स्टेट कैपिटल रीजन' ने रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रायपुर सहित दुर्ग-भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर के क्षेत्र कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। यह पूरा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर विकसित होगा।

भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के केन्द्र में स्थित होने के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की यह पहल पर स्टेट कैपिटल रीजन में योजनाबद्ध और शहरी विकास की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, स्टेट कैपिटल रीजन को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे राजधानी और आसपास के शहरों का प्लान्ड डेव्हलपमेंट होगा। साथ ही शहरी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य के लिए बेहतर और अनुकूल वातावरण तैयार होगा। इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी।

स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल शहरों में वर्ष 2031 तक 50 लाख से अधिक की आबादी रहने का अनुमान है। बढ़ते शहरीकरण और आबादी के दबाव को कम करने तथा बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहां राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करने का प्रावधान रखा गया है। यह प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि के अनुरूप होगा।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, राज्य के मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के सचिव, राज्य शासन द्वारा नामित सदस्यों में राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार विधायक, स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले चार निर्वाचित सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसके सदस्य संयोजक होंगे।

यह प्राधिकरण भूमि का प्रभावी उपयोग और पर्यावरण अनुकूल योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करेगा। वर्ष 2024-25 के बजट में स्टेट केपिटल रीजन कार्यालय की स्थापना के लिए सर्वेक्षण एवं डीपीआर बनाने के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य के लिए भी 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य राजधानी और आसपास के शहरों के व्यापक विकास के लिए योजना बनाने के साथ नियामक और समन्वय सस्थान के रूप में कार्य करना है। इसके प्रमुख कार्यों में स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाना, निवेश, आर्थिक योजनाओं और इनका कार्यान्वयन, विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के बीच समन्वय, आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देना भी है।

प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। इसके अलावा नगर तथा ग्राम निवेश के संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग के विकास संचालक, शहरी योजनाकार, अभियंता, वित्त, संपदा, पर्यावरण नामांकित सदस्य होंगे। इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में शामिल सभी जिलों के कलेक्टर इसके सदस्य होंगे।

स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा राजधानी क्षेत्र विकास निधि बनाई जाएगी। इसके साथ ही एक पुनरावृत्ति निधि भी होगी। इसे राजधानी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष उपकर लगाने की शक्ति भी होगी। यह वार्षिक बजट भी तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना एवं प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा।

रणनीति बनाम रणनीति

दो दृष्टिकोण, दो रास्ते

7 जुलाई 2025 — यह कोई साधारण तारीख नहीं, बल्कि छत्तीसगढ की राजनीतिक दिशा को नया मोड़ देने वाली घटना बन गई। एक ही दिन, दो मंच, दो रणनीतियाँ — कांग्रेस और भाजपा ने राज्य के दो भिन्न भूगोलों में, दो भिन्न दृष्टिकोणों के साथ एक साथ शक्ति प्रदर्शन किया। रायपुर में जहाँ कांग्रेस ने 'किसान, जवान, संविधान' जनसभा के ज़रिए भावनाओं का उभार किया, वहीं मैनपाट के शांत वनांचल में भाजपा ने तीन दिवसीय चिंतन शिविर के माध्यम से संगठनात्मक गहराई और चुनावी रोडमैप की नींव डाली।

यह सिर्फ एक 'राजनीतिक आयोजन' नहीं था, बल्कि दो विपरीत वैचारिक शक्तियों के बीच 2028 विधानसभा चुनाव की पूर्वपीठिका थी — जहाँ भावनाएं, संगठन, जनसंवाद और वैचारिक दृढ़ता एक निर्णायक संग्राम में बदलने की ओर अग्रसर हैं।

चिंतन शिविर से मिशन 2028 की शुरूआत

मैनपाट — सरगुजा की पहाड़ियों पर बसा, जहां प्रकृति के मध्य भाजपा ने आत्मावलोकन और रणनीति की थाली पर अगली चुनावी रणनीति को परोसा।

चिंतन शिविर की मुख्य धारणाएँ

बूथ सशक्तिकरण- कार्यकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण जिसमें 'बूथ जीतो ङ्क चुनाव जीतो' का फार्मूला दोहराया गया।

सोशल नेटवर्क का पुनर्गठन-सोशल मीडिया पर कांग्रेस के हमलों का उत्तर देने के लिए डिजिटल योद्धाओं की फौज तैयार करने की योजना।

वैचारिक स्पष्टता-हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, और विकास के 'त्रिदेव' को दोबारा उभारने की रणनीति।

'मिशन 2028' का रोडमैप-केवल 2026 की हार की समीक्षा नहीं, बल्कि 2028 तक सत्ता में पुन: वापसी का खाका।

जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति ने यह स्पष्ट किया कि भाजपा अब 'दिल्ली आधारित रणनीति' नहीं, बल्कि 'छत्तीसगढ़ विशेष' संगठन के बलबूते वापसी की तैयारी में है।

रायपुर से संवैधानिक जनजागरण की हुंकार

साइंस कॉलेज मैदान, रायपुर — जहां बारिश की बूँदें भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह को नहीं रोक सकीं। कांग्रेस ने यहाँ न केवल अपने परंपरागत जनाधार को जगाने की कोशिश की, बल्कि संविधान के नाम पर एक वैचारिक लड़ाई की शुरुआत की। तीन स्तंभ — किसान, जवान, संविधान=

- **किसान**-फसल बीमा, कर्ज़ माफी, खाद्य सुरक्षा — इन तीन बिंदुओं पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधा हमला।
- **जवान**- अग्निपथ योजना, पुरानी पेंशन, और सेना में भर्तियों के मुद्दे के ज़रिए राष्ट्रवाद की भाजपा परिपाटी को चुनौती।
- **संविधान**- दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को केन्द्र में रखकर कांग्रेस ने अपने 'संविधान रक्षक' स्वरूप को उभारा।

यह सभा कांग्रेस के लिए केवल एक भावनात्मक बयान नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्संरचना का चरण था। खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की नई 'संविधान-केन्द्रित' लाइन अब भाजपा के हिंदुत्व विमर्श के समानांतर एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस के भीतर की चालें

1. भूपेश बघेल - जनाधार और ज़मीनी ताक़त का चेहरा

कार्यकर्ताओं की भागीदारी, सभा का प्रबंधन, और मीडिया कवरेज - इन सभी में भूपेश बघेल की सक्रियता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। वे न केवल अपने पुराने जनाधार को फिर से सक्रिय

कर रहे हैं, बल्कि आदिवासीङ्गओबीसी गठजोड़ को भी मज़बूत कर रहे हैं।

2. चरणदास महंत – वैचारिक स्थिरता और ब्राह्मण नेतृत्व

महंत ने सभा में संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाकर कांग्रेस की विचारधारा को बल दिया। हालांकि उनका संवाद अधिक सैद्धांतिक था, लेकिन पार्टी के अंदरूनी संतुलन में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।

3. दीपक बैज– आदिवासी समन्वय और संगठनात्मक अनुशासन

प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैज ने इस आयोजन को ज़मीनी स्तर पर जोड़ने का कार्य किया। उनकी रणनीति स्पष्ट थी — खड़गे के राष्ट्रीय नेतृत्व को आदिवासी बेल्ट में प्रासंगिक बनाना और पार्टी के आंतरिक टकरावों को व्यावहारिक रूप से साधना।

सचिन पायलट और युवा सोच की प्रतिछाया

हालाँकि पायलट इस जनसभा में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे, लेकिन खड़गे के भाषण और युवा लक्षित एजेंडे में उनकी छवि स्पष्ट थी।

'रोजगार', 'संवैधानिक संरक्षण' और 'सामाजिक न्याय' जैसे मुद्दे इस सभा की रीढ़ थे — जो राष्ट्रीय मंच पर पायलट-राहुल-थरूर की विचारधारा के ही प्रतिरूप हैं।

सनातन बनाम संविधान विमर्श

भाजपा नेता विजय शर्मा का बयान — 'छत्तीसगढ़ सनातन विरोधियों का स्वागत नहीं करेगा' — कांग्रेस के सामाजिक न्याय एजेंडे को धर्म बनाम संविधान के मोर्चे पर धकेलने की रणनीति थी।

यह बयान केवल बयान नहीं था, बल्कि एक संकेत है कि आने वाले दिनों में भाजपा अपनी हिंदुत्ववादी भावनात्मक अपील को 'संवैधानिक अधिकारों के विमर्श' से टकराने की कोशिश करेगी।

संगठनात्मक चुनौतियाँ और जज़्बे की परीक्षा

साइंस कॉलेज मैदान में जलभराव, ट्रैफिक प्रबंधन की कमी और टेंट के नीचे फिसलन — ये सारी चुनौतियाँ कांग्रेस की प्रशासनिक तैयारी की सीमाओं को दिखाती हैं।

लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश, NSUI और महिला कांग्रेस की सक्रियता, और ज़िलावार क़ाफ़िले — यह सब दर्शाता है कि कांग्रेस मन से हारी पार्टी नहीं है, बल्कि जूझने वाली ताक़त है।

घोषणाओं से भरोसे की ओर

2023 के विधानसभा चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया था कि छत्तीसगढ़ की जनता अब नारे नहीं, नीतियाँ देखती है।

BJP — केंद्र की योजनाओं, वैचारिक स्पष्टता और संगठनात्मक मज़बूती से भरोसा जीतना चाहती है।

Congress — जनभावनाओं, क्षेत्रीय मुद्दों और संविधान-संरक्षण के नारे से अपने आधार को पुनर्जीवित कर रही है।

लेकिन इस बार चुनाव केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि भरोसे और प्रदर्शन के आधार पर लड़ा जाएगा।

छत्तीसगढ़ की राजनीति एक निर्णायक चौराहे पर

7 जुलाई 2025 – एक तारीख जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को दो दिशाओं में बाँट दिया।

भाजपा – संगठनात्मक मंथन और पुनरुद्धार की प्रक्रिया में है।

कांग्रेस – वैचारिक जनजागरण और जमीनी लड़ाई की मुद्रा में।

राज्य अब विचारधारा, जनभावना, संगठन और संघर्ष के चार स्तंभों पर टिका चुनावी संग्राम देखने जा रहा है। भविष्य उन्हीं का होगा जो जनता की ज़रूरत, उनकी असुरक्षा और उनके सपनों को समझते हुए भरोसे का सेतु बना सकें। संगठन और संघर्ष – चारों धाराएँ मिलकर अगली सत्ता की दिशा तय करेंगी।

बस्तर में फैल रहा है अब विकास का उजियारा

छत्तीसगढ़, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, घने वन क्षेत्र और विविध जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सलवाद की चुनौती से जूझता रहा है। बस्तर के विकास में बाधक रहे नक्सलवाद के अब यहां से नक्सल उन्मूलन की अंतिम लड़ाई जारी है। बस्तर संभाग अपनी कला एवं संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान रखता है अकेले बस्तर संभाग में ही हल्बी, गोड़ी, भतरी दोलरी जैसे पारंपरिक बोली, बोली जाती है। वर्षों से अशांत रहे बस्तर अंचल में ढोल और मांदर की थाप अब फिर से सुनाई देने लगेगी। मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। सटीक रणनीति के साथ यहां आतंक के खात्मे और सामाजिक- आर्थिक विकास के काम हो रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों में जिस तरह लोगों ने भागीदारी की वो इस बात का प्रमाण है की बस्तर में अब शांति स्थापित हो रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मानना है कि ''लाल आतंक के खात्मे के लिए नक्सलियों के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई जोर शोर से जारी है। इसका परिणाम है कि नक्सलियों की कमर अब टूट गई है। प्रदेश से जब तक नक्सली हिंसा और उग्रवाद का अंत नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे।''

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून 2025 को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे इस दौरान उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के वीर जवान कठिन चुनौतियों और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद नक्सलवाद के खात्मे के अभियान को ऐतिहासिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों का अद्वितीय साहस और बलिदान न केवल हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा को प्रदर्शित करता है, बल्कि पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि हमारा देश अब नक्सलवाद की बेड़ियों से मुक्त होने की ओर अग्रसर है।

छत्तीसगढ़ में बीते 21 मई 2025 को माओवादी सरगना बसव राजू के साथ अबूझमाड़ के जंगल में 26 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों के

> "मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मानना है कि ''लाल आतंक के खात्मे के लिए नक्सलियों के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई जोर शोर से जारी है। इसका परिणाम है कि नक्सलियों की कमर अब टूट गई है। प्रदेश से जब तक नक्सली हिंसा और उग्रवाद का अंत नहीं हो जाता हम चुप नहीं बैठेंगे।"

हाथों मारे जाने से नक्सलवाद की कमर टूटी है। इस पर सवा 3 करोड़ का ईनाम घोषित था। तीन दशकों में पहली बार हुआ है कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया। यह असाधरण कामयाबी है और इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नक्सल के ताबूत में हमने अंतिम कील जड़ दिया है। इसके अलावा शीर्ष ईनामी नक्सली लक्ष्मी नरसिम्हा चालम उर्फ सुधाकर भी 05 जून 2025 को नेशनल पार्क एरिया में पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया गया, इस पर 1 करोड़ का ईनाम था। नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना नक्सल प्रभावित इलाकों में गेम चेन्जर साबित हो रही है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित नए कैम्पों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों एवं ग्रामीणों को 17 विभागों की 59 हितग्राहीमूलक योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं के तहत आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋ़ण मिलेगा।

प्रदेश में पिछले डेढ़ साल के भीतर सुरक्षाबलों ने अपनी बहादुरी से 438 नक्सलियों को मार गिराया है। साथ ही 1515 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और 1476 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर विवश किया है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे सुरक्षा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से हमारी सरकार अंदरूनी गांवों तक सुरक्षा के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच भी सुनिश्चित करने में सफल हो रहे हैं।

आखिर क्यों खास है पूवर्ती गांव

सुकमा जिले के अंदरूनी व अतिसंवेदनशील क्षेत्र में बसा हुआ पूवर्ती गांव एक वक्त नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था। एक करोड़ रुपए का ईनामी नक्सली हिड़मा तथा टेकलगुड़ा कैंप निर्माण के दौरान नक्सली हमले की घटना का मास्टरमाइंड देवा का यह पैतृक गांव होने के कारण हमेशा चर्चा में रहा है। माओवादियों का प्रभाव में होने के कारण पूवर्ती गांव में शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब इस गांव में सुरक्षा कैम्प खुलने से यहां के लोगों को तेजी से मूलभूत सुविधाएं सुलभ होने लगी है।

आदिवासी बाहुल्य आबादी, अनुपम नैसर्गिक सुंदरता और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बस्तर में आज विकास का सबसे बढ़ा अवरोधक है नक्सली हिंसा। पिछले 3 दशकों में नक्सलियों ने यहां अपने पैर पसारे। बंदूक के दम पर हिंसा के साथ विकास कार्यों में बाधा पहुंचाई।

नक्सलियों ने अपने झूठे, खोखले सिद्धांतों के जरिए लंबे समय तक भोले-भाले आदिवासियों को भ्रम में डाला, हिंसा का सहारा लेकर उन्हें डराने की कोशिश की। बच्चों से उनके स्कूल छीने, उनका बचपन छीना उन्हें हिंसा की राह पर धकेला। कई परिवारों को बर्बाद किया, सुहागनों की सिंदूर उजाड़े, बेटियों को अगवा किया और उन्हें भी हिंसा के रास्ते पर ले गए। इसी वजह से संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर पर देश के सबसे पिछड़े इलाकों में एक होने का धब्बा लगा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ विकास के इस अवरोध को पूरी तरह से समाप्त करने पर डटी हुई है।

3100 रुपये का वादा, 6000 करोड़ की उलझन

'किसानों को लाभ देना हमारा दायित्व है, लेकिन हम केंद्र सरकार से भी विशेष आर्थिक सहायता की माँग कर रहे हैं, क्योंकि यह संकट अब राज्य की क्षमता से बाहर हो गया है।'

विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री

'120 रुपये क्विंटल के हिसाब से लागत तो आती है, लेकिन 12 महीने हो गए पैसा नहीं मिला। हमसे बार-बार गारंटी और चावल मांगते हैं, लेकिन भुगतान नहीं देते।'

-सुबोध अग्रवाल, मिलर (राजनांदगांव)

छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' यूँ ही नहीं कहा गया। यह सिर्फ एक उपमा नहीं, बल्कि राज्य की पहचान, आत्मा और अर्थव्यवस्था की नींव है। लेकिन 2024-25 के खरीफ विपणन वर्ष में यही धान अब संकट की गुत्थी बन गया है। यह संकट अब सिर्फ खेत-खलिहानों का नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों, गोदामों की क्षमता, मिलर्स की हड़ताल और किसानों की उम्मीदों का परीक्षण बन चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के खरीफ विपणन वर्ष में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद कर देशभर में सबसे ऊँचा समर्थन मूल्य तय किया। जबकि केंद्र सरकार ने सामान्य किस्म के धान का MSP मात्र रू.2183 तय किया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें लगभग रू.917 की अतिरिक्त सहायता दी।

फैसले ने किसानों को तो राहत दी, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर राज्य सरकार के लिए यह निर्णय भारी पड़ने लगा। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 104.48 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य था, जिसमें से 70 लाख टन चावल FCI और 14.3 लाख टन NAFED या नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) को देना प्रस्तावित था। जिसमें से खरीदी 101.60 लाख टन (31 मार्च 2025 तक) हो चुकी थी। मगर इनमें से 30 से 33 लाख टन धान ऐसा है जिसे न केंद्र ने खरीदा, न बाजार ने और न ही पर्याप्त भंडारण।— वह राज्य के पास अधिशेष है।

गोदामों का संकट और सड़ता धान

जनवरी 2025 में खरीदी चरम पर थी। अनुमान था कि उस वक्त तक 50-60 लाख टन धान और 10-15 लाख टन चावल पहले से ही भंडारण में था। मार्च आते-आते यह आँकड़ा और बढ़ा। जून तक हालात ऐसे हो गए कि 10-15 लाख टन धान और 10-12 लाख टन चावल गोदामों में बिना प्रसंस्करण के पड़ा रह गया।

नान (NAN) के गोदाम भर चुके हैं, और मानसून की बारिशों के बीच खुले में पड़ा धान अब खराब होने की कगार पर है। यदि यही स्थिति बनी रही तो लाखों क्विंटल अनाज सिर्फ इसलिए सड़ सकता है क्योंकि सरकार के पास इसे बचाने का न तो स्थान है और न ही व्यवस्था।

भुगतान की उलझन

धान से चावल बनाने की प्रक्रिया 'कस्टम मिलिंग' कहलाती है, जिसे राज्यभर की राइस मिलें अंजाम देती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के अनुसार राज्य सरकार पर मिलर्स की लगभग रू 6000 करोड़ की बकाया राशि है। यह बकाया मिलिंग चार्ज, परिवहन, प्रोत्साहन राशि, भंडारण और अन्य खर्चों का है। 2024 में मिलर्स ने हड़ताल की थी और सरकार ने रू 1200 करोड़ की आंशिक राशि जारी की, लेकिन मिलर्स का कहना है कि 'अब और उधार पर काम संभव नहीं'। मिलर्स को मजदूरी, ट्रांसपोर्ट, बैंक गारंटी जैसे खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। कई मिलों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें भुगतान नहीं मिला तो वे आगामी मिलिंग कार्य नहीं करेंगे।

सरकार की दुविधा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार दो पाटों के बीच फंसी हुई है- एक ओर किसान हैं, जो समर्थन मूल्य पर समय पर भुगतान चाहते हैं; दूसरी ओर मिलर्स हैं, जो बिना भुगतान के कस्टम मिलिंग नहीं करेंगे।

इस दुविधा में सबसे बड़ा संकट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। यदि मिलिंग नहीं होती, तो न केवल धान सड़ेगा, बल्कि अगले वर्ष की खरीदी भी ठप हो सकती है। और यदि किसानों को समय पर भुगतान नहीं हुआ तो उनकी क्रय शक्ति, बोवाई, और मानसून आधारित खेती पर असर पड़ेगा।

राजकोषीय प्रबंधन को देखते हुए राज्य सरकार का घाटा पहले से ही त्तस्छ्रक्क का 3.8त्न छू चुका है, जो स्न्नक्रक्चरू एक्ट की सीमा के करीब है। इसलिए राज्य सरकार बिना केंद्र की मदद के इतने बड़े बकाए का भुगतान कर पाना मुश्किल मान रही है।

धान की राजनीति से नीति की दिशा तय होगी

छत्तीसगढ़ की आत्मा खेतों में बसती है। इस राज्य की समृद्धि धान के दानों में नहीं, बल्कि उन दानों से जुड़े किसान, मजदूर, मिलर्स और उपभोक्ताओं की आजीविका में है। यह संकट केवल 'सरकारी खरीदी' का मामला नहीं है — यह उस संरचना की परीक्षा है, जिसने छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाया।

यदि समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिए गए, तो यह संकट केवल गोदामों तक नहीं, बल्कि गाँव के हर घर तक पहुंचेगा — और राज्य के आर्थिक संतुलन को हिला कर रख देगा।

कांग्रेस की चुप्पी और भूपेश की तन्हाई

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस डो खेमों मे बाँटी दिखी एक भूपेश के साथ जो अब भी मानता है कि चैतन्य की गिरफ्तारी 'राजनीतिक प्रतिशोध' है। उनके लिए यह 'बेटे की नहीं, साजिश की लड़ाई' है। तो दूसरा खेमा चुप, लेकिन सचेत ।उसे शायद स्पष्ट है कि चैतन्य कोई पार्टी पदाधिकारी नहीं है। यह गिरफ्तारी एक परिवार का मामला है, पार्टी का नहीं। और संगठन की यह चुप्पी – सिर्फ चुप्पी नहीं है। यह संकेत है।

22 जुलाई 2025 — तारीख वही थी, मंच वही, झंडे वही... लेकिन आत्मा गायब थी। सड़कों पर बारिश थी, पोस्टर थे, थोड़ी बहुत हलचल थी — लेकिन अगर कुछ नहीं था, तो वो था 'विश्वास'। रायपुर की सड़कों पर जो नज़र आना चाहिए था — जनांदोलन, उत्तेजना, भीड़ की हुंकार, सत्ता के विरुद्ध हुंकार — उसकी जगह केवल पानी था, मौन था, और बिखरती हुई एकता थी। कांग्रेस की जिस आर्थिक नाकेबंदी की बात की गई, वो असल में एक सजीव नाटक था — बिना दर्शकों के, बिना उत्साह के, और सबसे महत्वपूर्ण — बिना राजनीतिक आत्मा के।

यह आर्थिक नाकेबंदी थी या भावनात्मक औपचारिकता?

जब कांग्रेस ने एलान किया कि वह 'ED की कार्रवाई के खिलाफ राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी' करेगी, तो राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे 'भूपेश की वापसी की रणनीति' माना। लेकिन जो हुआ — वह कांग्रेस की ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संगठन के भीतर की भावनात्मक दूरी का सार्वजनिक उद्घाटन था। नारे थे, लेकिन उनमें आग नहीं थी। जुलूस था, मगर नेतृत्व को देखने की ललक नहीं थी। और सबसे बड़ी बात — कार्यकर्ता थे, लेकिन आत्मा गायब थी। बारिश में भीगते हुए लोग कम थे, नारे खोखले थे, और कार्यकर्ता या तो अपने घरों में थे, या किराए पर बुलाए गए थे। कांग्रेस की यह 'नाकेबंदी' दरअसल एक युग की नाकामी का प्रतीक बन गई।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस डो खेमों मे बाँटी दिखी एक भूपेश के साथ जो अब भी मानता है कि चैतन्य की गिरफ्तारी 'राजनीतिक प्रतिशोध' है। उनके लिए यह 'बेटे की नहीं, साजिश की लड़ाई' है।

तो दूसरा खेमा चुप, लेकिन सचेत ।उसे शायद स्पष्ट है कि चैतन्य कोई पार्टी पदाधिकारी नहीं है। यह गिरफ्तारी एक परिवार का मामला है, पार्टी का नहीं। और संगठन की यह चुप्पी — सिर्फ चुप्पी नहीं है। यह संकेत है।

गिरफ्तारी-चैतन्य की या भरोसे की?

22 जुलाई के प्रदर्शन से एक दिन पहले ही, राज्य की आर्थिक राजधानी बिलासपुर से लेकर बस्तर तक, कई नए नाम छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सामने आए। ईडी और इनकम टैक्स की संयुक्त कार्रवाई में 13 से अधिक अधिकारियों और कारोबारी दलालों को हिरासत में लिया गया।

सूत्र बताते हैं कि कुछ गिरफ्तार लोगों के मोबाइल से चैतन्य बघेल और उनके करीबी सहयोगियों के संवाद और लेन-देन के प्रमाण मिले हैं।

इस घोटाले की जड़ में क्या है?

2020ङ्क2023 के बीच सरकारी शराब बिक्री के नाम पर फर्जी कंपनियाँ बनाई गईं।

टेंडर प्रक्रिया में बदलाव कर निजी ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया गया।

शराब दुकानों से दैनिक 'कट' की व्यवस्था बनाकर पैसे को राजनीतिक फंडिंग में इस्तेमाल किया गया।

इस पूरे नेटवर्क में पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोग, कुछ ब्रूस अधिकारी, और एक खास 'युवराज' मंडली का नाम सामने आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कोई अचानक आई आँधी नहीं थी। शराब घोटाले की परतें महीनों से खुल रही थीं — श्रष्ठ की फाइलें, लोकायुक्त की नोटिंग्स, और मीडिया में लीक होती जाँच रिपोर्ट्स — सब कुछ एकतरफा नहीं था।

अब तक की मुख्य गिरफ्तारियाँ

IAS अफसर अंकित आनंद – घोटाले की नीतिगत संरचना में संलिप्तता।

शराब कारोबारी दीपक वर्मा – 700 करोड़ से ज़्यादा की हेराफेरी में आरोपी।

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व अधिकारी – सीलबंद बोतलों में बेईमानी की गंध।

और अब **चैतन्य बघेल** – 'बेटे' की भूमिका क्या थी, यह सवाल सबके मन में है, जवाब भूपेश के पास होना चाहिए।

लेकिन जवाब नहीं मिला।

मिला तो सिर्फ एक रटा-रटाया बयान- 'यह साज़िश है। बदनाम करने की कोशिश है।' लेकिन संगठन चुप रहा — इतना चुप कि अब यह चुप्पी खुद एक बयान बन गई है।

तो फिर कांग्रेस क्यों चुप है?

क्योंकि यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है — यह पार्टी की नैतिक साख पर उठा सवाल है। एक समय था जब भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में मसीहा जैसे थे — 2018 में उनकी नेतृत्व में कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की। लेकिन सत्ता का चरित्र व्यक्ति का नहीं, संगठन का मूल्यांकन करता है। जब गिरफ्तारी हुई तो ना कोई संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, ना दिल्ली से कोई वरिष्ठ नेता आए, ना राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। और जो बोले — उन्होंने कहा- 'यह बदनाम करने की साजिश है।' पर जनता ने पूछा — साजिश किसकी? और पार्टी ने जवाब नहीं दिया।

कार्यकर्ता भावुक नहीं हुआ, क्योंकि उसे दिशा नहीं मिली

राजनीति में भावना से बड़ी होती है दलील। जब कार्यकर्ता सड़कों पर उतरता है, तो उसे साफ समझ चाहिए कि वह किसके लिए लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, और उस लड़ाई में संगठन उसके साथ खड़ा है या नहीं। 22 जुलाई को न तो नेता अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्टीकरण देने पहुंचे, न चैतन्य की तरफ़ से कोई स्पष्ट माफ़ी या सफ़ाई आई, न ही कोई ठोस रणनीति बनाई गई। सिर्फ एक भावनात्मक अपील —'हमारे बेटे को फँसाया गया है'— लेकिन कोई प्रमाण नहीं।

संघर्ष का संकल्प या व्यक्तिगत पिकनिक?

रायपुर के प्रदर्शन में एक दृश्य ऐसा भी था–

कार्यकर्ता सड़क किनारे चाय की दुकान पर हंसी-ठिठोली करते दिखे।

कुछ युवा 'बारिश में भीगकर' सेल्फी लेते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे।

यह प्रदर्शन नहीं था — प्रहसन था। और यही दर्शाता है कि यह लड़ाई अब न संगठन की रही, न जनता की — यह केवल एक अतीत से चिपके नेता की तड़प बन गई है। भूपेश बघेल अगर चाहते हैं कि यह कांग्रेस की लड़ाई बने — तो उन्हें सबसे पहले कांग्रेस को भरोसे में लेना होगा।

साफ-साफ बताना होगा कि शराब घोटाले में उनका या उनके परिवार का क्या रोल है या नहीं है।

कार्यकर्ताओं को दलील देनी होगी — सिर्फ भावुकता नहीं।

संगठन के निर्णयों को स्वीकार करना होगा — अगर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे रोकने की कोशिश न करें।

यह चैतन्य की गिरफ्तारी नहीं... यह चेतावनी है।

चेतावनी कि- जो नेता सत्ता से उतरते ही संगठन से भी कट जाए — वह नेता नहीं, केवल एक किरदार होता है। और किरदार, समय के साथ बदल दिए जाते हैं।

यह केवल गिरफ्तारी की बात नहीं है। यह एक युग के अंत की घोषणा है। सत्ता के ताज के साथ जो चमक आती है, वह ताज उतरते ही बिलकुल वैसे ही गायब हो जाती है, जैसे बारिश के बाद बिछी धूल। अगर भूपेश बघेल अब भी इस भ्रम में हैं कि जनता और कार्यकर्ता उनके साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे 2018 में थे — तो यह भ्रम उनका सबसे बड़ा राजनीतिक आत्मघात बन सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि चैतन्य दोषी है या निर्दोष।

सवाल यह है कि भूपेश —

क्या आप विश्वास के उस संकट को समझ पाएँगे, जो अब पार्टी में भी है, और जनता में भी? क्योंकि आज नहीं तो कल, कांग्रेस को भूपेश से पूछना ही होगा — 'अब बहुत हुआ... क्या अब आप खुद हटेंगे, या पार्टी को हटाना पड़ेगा?'

CGMSC की कार्यप्रणाली पर उठते सवाल

रायपुर. छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं और उपकरणों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में Phenytoin Sodium Injection को अमानक करार देते हुए उसके उपयोग और वितरण पर रोक लगाई गई है। इससे पहले प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक किट और इंट्रावीनस ड्रिप सेट भी गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो चुके हैं। यह स्थिति केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर ही नहीं, बल्कि राज्य की जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति प्रणाली पर भी एक गहरा प्रश्नचिह्न है।

जीवन रक्षक, अब जोखिम भरा

Phenytoin Sodium का उपयोग मिर्गी के झटके और सिर पर चोट लगने के बाद उत्पन्न होने वाले झटकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह दवा कई मरीजों को लाइफ-लॉन्ग थेरेपी के तौर पर दी जाती है। CGMSC द्वारा सिस्टोग्राम लैबोरेट्रीज लिमिटेड से प्राप्त इस दवा को पहले परीक्षण में अमानक पाया गया था, परंतु अब दोबारा जांच में भी यह फेल हो गई। फलस्वरूप इसे सभी अस्पतालों और संस्थानों से वापस मंगाने का आदेश दिया गया है।

पहले भी आई थीं गुणवत्ता संबंधी शिकायतें

CGMSC द्वारा सिस्टोग्राम लैबोरेट्रीज लिमिटेड से प्राप्त Phenytoin Sodium इंजेक्शन पहले परीक्षण में ही अमानक पाया गया था, इसके बावजूद यह गोदामों और अस्पतालों तक पहुँचा। इसका मतलब यह है कि सप्लाई चेन और परीक्षण प्रक्रिया में कोई बड़ी खामी रही होगी। दो बार फेल हो चुके इस इंजेक्शन का वितरण किया गया—यह दर्शाता है कि प्रदेश की गुणवत्ता जांच प्रणाली सिर्फ दस्तावेज़ों तक सीमित रह गई है।

वैसे यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले CGMSC ने प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक किट और इंट्रावीनस ड्रिप सेट के उपयोग और वितरण पर रोक लगाई थी। इन उत्पादों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते रहे। प्रेगनेंसी टेस्ट किट, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सबसे अधिक प्रयोग होती है, यदि वह गलत परिणाम देती है तो इससे न केवल चिकित्सा में भ्रम पैदा होता है बल्कि महिलाओं के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर होता है। इसी प्रकार इंट्रावीनस ड्रिप सेट, जब्लड , सलाइन, या जीवन रक्षक दवाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है, यदि गुणवत्ता विहीन हो तो सीधा प्रभाव मरीज की नसों और शरीर पर होता है।

CGMSC जो राज्य की प्रमुख दवा और मेडिकल उपकरण क्रय संस्था है, का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य संस्थानों तक सुरक्षित, प्रभावी और मानक चिकित्सा उत्पाद पहुँचें। लेकिन यदि खुद यही संस्था अमानक उत्पादों की आपूर्ति कर रही है, तो यह दो स्तरों पर विफलता है-

गुणवत्ता नियंत्रण में चूक

कॉन्ट्रैक्टर/वेंडर चयन में लापरवाही या भ्रष्टाचार

यह आशंका निर्मूल नहीं है कि क्या लाभ की दौड़ में कुछ कॉर्पोरेट्स की लापरवाही या भ्रष्ट तंत्र की अनदेखी इसके पीछे है? इन घटनाओं के बाद स्वास्थ्य विभाग और CGMSC की जिम्मेदारी बनती है कि वे सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करें

मरीजों का जीवन, डॉक्टर की नैतिक दुविधा

राज्य के दूरदराज इलाकों में जहां मिर्गी, सिर की चोटें, गर्भधारण जैसी स्थितियों में त्वरित इलाज ही जीवन रक्षक होता है, वहाँ ऐसी घटनाएं मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ से कम नहीं। कोई मरीज यदि अमानक दवा लेकर झटका न रुकने या गलत गर्भ परीक्षण से गुज़रे, तो उसका मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है।

इस तरह की घटनाओं से सबसे बड़ा नुकसान मरीजों को होता है। डॉक्टर जो दवा लिख रहे हैं, वह मानकर चल रहे हैं कि वह प्रभावी है — लेकिन जब वही दवा अमानक निकलती है, तो इलाज की पूरी प्रक्रिया असफल हो जाती है। इससे डॉक्टरों की नैतिक दुविधा, मरीजों की सेहत, और स्वास्थ्य संस्थाओं की साख तीनों पर गहरा असर पड़ता है।

दोषी सप्लायर्स पर क्या कार्रवाई की गई?

- अगली खेप की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?
- अस्पतालों में पहले से वितरित सामग्री से हुई किसी क्षति या रुग्णता की समीक्षा हुई या नहीं?
- अब तक विभागीय नोटिस, प्रतिबंध आदेश और गोदाम में वापसी जैसे प्रतिसादी कदम ही दिखाए गए हैं, लेकिन प्रिवेंटिव या सुधारात्मक उपायों की पारदर्शिता नदारद है।

नीति सुधार की आवश्यकता

- **थर्ड पार्टी क्वालिटी टेस्टिंग को अनिवार्य बनाना-** किसी भी सप्लाई से पहले एक स्वतंत्र प्रयोगशाला से परीक्षण होना चाहिए।
- **ब्लैकलिस्टिंग और दंड की पारदर्शी प्रक्रिया-**जो कंपनियां एक बार अमानक उत्पाद देती हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
- **लोकसभा / विधानसभा स्तर पर निगरानी समिति का गठन-** जो CGMSC जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली की सतत समीक्षा करे।
- **जनहित में पारदर्शिता-** ऐसी सूचनाएं केवल संस्थानों तक सीमित न रहकर जनसामान्य तक खुली होनी चाहिए, ताकि जनता को जानकारी रहे कि कौन-सी दवा या उपकरण असुरक्षित है।

CGMSC द्वारा लगातार तीसरी बार अमानक दवा या उपकरण की सप्लाई सामने आना न केवल संस्थागत असफलता है, बल्कि यह उस जन विश्वास को भी तोड़ता है जो आम नागरिक सरकारी अस्पतालों पर रखता है। ऐसे में अब 'आदेश जारी करने' से ज्यादा जरूरी है 'व्यवस्था की आत्म-पुनर्रचना'। यह सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की नैतिक परीक्षा भी है—जहाँ जान बचाना सिर्फ डॉक्टरी जिम्मेदारी नहीं, नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए।

42000 सपनों की धज्जियां, सिस्टम की परीक्षा फेल

'जब सिस्टम फेल होता है, तब केवल प्रक्रियाएं नहीं टूटतीं - टूटते हैं सपने, संघर्ष और विश्वास।' छत्तीसगढ़ की वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया इस कथन का जीवंत उदाहरण बन चुकी है। साल 2023-24 के अंतर्गत निकाली गई 1484 पदों की सीधी भर्ती में करीब 4.15 लाख युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन आज स्थिति यह है कि 42000 से अधिक अभ्यर्थी खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की यह बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया शुरुआत से ही अव्यवस्था की चपेट में रही। पहली बार फिजिकल टेस्ट कराए गए, लेकिन... 17 नोडल मंडलों में से 9 मंडलों में लंबी कूद की परीक्षा मैन्युअल करवाई गई - बिना किसी डिजिटल रिकॉर्ड के। वहीं 12 मंडलों में 6979 अभ्यर्थियों से रात में कृत्रिम प्रकाश में टेस्ट लिया गया - जबकि नियम साफ़ कहते हैं कि फिजिकल टेस्ट केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही लिए जा सकते हैं।

यह तकनीकी गड़बड़ी थी लापरवाही?

फिजिकल टेस्ट में स्पष्ट अनियमितताओं के बाद भी विभाग ने उसे मान्य घोषित कर दिया। लेकिन युवाओं के विरोध और सवालों के बाद 7 जुलाई को दोबारा फिजिकल टेस्ट की घोषणा की गई। पर यहां भी 'इंसाफ' नहीं मिला, बल्कि... राजनांदगांव में 2273 अभ्यर्थी तेज़ बारिश में रात में ही शहर पहुंचे, ताकि सुबह ग्राउंड में टेस्ट दे सकें। सुबह 4 बजे जब वे नवागांव मैदान में पहुँचे, तो पता चला कि बारिश से ग्राउंड गीला है, परीक्षा रद्द।

क्या एक गरीब किसान का बेटा, जो किराया, खानपान और ठहरने का खर्च उठाकर आया, उसे केवल 'आगामी आदेश तक परीक्षा स्थगित' कहकर लौटा देना न्याय है?

जब ज़रूरत थी तब टेक्नोलॉजी कहाँ थी?

2024 में भी मैन्युअल स्टॉपवॉच, कागज़ पर माप, और कृत्रिम रोशनी में जजमेंट — यह सब उस वक्त हुआ जब डिजिटल उपकरणों की अनिवार्यता भर्ती नियमों में दर्ज है। तो क्या विभागीय मशीनें खराब थीं?

या नियोजन ही इतना 'अव्यवस्थित' था कि सिस्टम ने खुद को अराजकता के हवाले कर दिया?

4 लाख आवेदन, 2.5 लाख अनुपस्थित - क्यों?

क्या कभी आपने सुना है कि किसी सरकारी भर्ती में इतने mass absenteeism हो? क्यों 4.15 लाख में से केवल 1.5 लाख ही फिजिकल टेस्ट देने पहुँचे? क्या विभाग की सूचना प्रणाली फेल हुई? या युवा पहले ही निराश हो चुके थे?

कठघरे में सवाल

क्या वन विभाग खुद नियमों की अनदेखी कर रहा है? दोबारा परीक्षा करवाने के बाद भी व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधरीं? क्या इस 'अनियमित फिजिकल टेस्ट' के ज़रिये किसी खास वर्ग को फायदा पहुँचाने की कोशिश हुई? जिन अभ्यर्थियों ने लाखों खर्च करके दो बार फिजिकल टेस्ट दिया- उन्हें क्या मानसिक मुआवजा मिलेगा?

युवा बोलेगा तो सरकार बोलेगी!

छत्तीसगढ़ की सड़कों पर युवाओं के प्रदर्शन से सत्ता अभी तक आंख चुरा रही है। लेकिन अब यह परीक्षा सिर्फ युवाओं की नहीं, लोकतंत्र की भी है - क्या एक युवा जो 'वनरक्षक' बनकर पर्यावरण और समाज की रक्षा करना चाहता है, उसका सपना भी इसी तरह लापरवाही और तकनीकी बहानों में दफन होगा? इस पूरी प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रणाली एक गंभीर सुधार और उत्तरदायित्व की माँग करती है। सिर्फ परीक्षा करवा देने से नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं को पारदर्शी, वैज्ञानिक और संवेदनशील बनाकर ही युवाओं का विश्वास पुन: अर्जित किया जा सकता है।

लाईफवर्सिटी

संघ-भाजपा में नेतृत्व का सूर्योदय या सूर्यास्त?

मोहन भागवत का 16 वर्ष का कार्यकाल एक युग रहा है—संघ के भीतर और बाहर दोनों जगह। यदि वे शताब्दी वर्ष से पहले स्वयं पद से निवृत्त होते हैं, तो यह संघ की परंपरा को नई वैधता देगा। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं और सत्ता में बने रहते हैं, तो यह संघ-भाजपा संबंधों में सबसे बड़ी वैचारिक दरार बन सकती है।

'जब कंधों पर शॉल डाली जाने लगे, तो समझना चाहिए कि सेवा का तरीका बदलने का वक्त आ गया है...'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत का यह वाक्य, किसी साधारण वक्तव्य की तरह नहीं, बल्कि राजनीतिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में एक गहरी हलचल पैदा करने वाला संकेत बन चुका है। मंच पर पुस्तक थी, स्मरण था वरिष्ठ प्रचारक मोरोपंत पिंगले का, लेकिन शब्दों के पीछे जो मर्म छिपा था, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को बेचैन कर दिया है। आखिर, यह कथन ऐसे समय आया है जब स्वयं भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी—दोनों ही 75 की आयु सीमा को छू रहे हैं। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता।

हालाँकि RSS में कोई लिखित नियम नहीं है कि 75 पार करने के बाद पद छोड़ना चाहिए, लेकिन एक विचारधारा-संस्थागत परंपरा के रूप में यह 'मर्यादा' स्थापित की जाती रही है। भाजपा में जब नरेंद्र मोदी सत्तारूढ़ हुए, तो वरिष्ठतम नेताओं—लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जैसे दिग्गजों को 75 की उम्र पार करते ही मार्गदर्शक मंडल की शोभा बना दिया गया। उस समय

> भारतीय राजनीति के लिए यह यथार्थ स्वीकार करना कठिन हो सकता है कि एक गैर-राजनीतिक संस्था (RSS) आज भी सत्ताधारी दल की दिशा और नेतृत्व तय करने की क्षमता रखती है। लेकिन यही संघ का स्वभाव है—'छाया में रहकर दिशा देना।'

इसे अनुशासन का पालन कहा गया था।

लेकिन अब सवाल है—क्या वही मापदंड नरेंद्र मोदी पर लागू होंगे?

संकेत केवल 'संकेत' नहीं होते

मोहन भागवत की बातों को महज़ एक व्यक्तिगत आत्मचिंतन के रूप में पढ़ना राजनीतिक मासूमियत होगी। यह वक्तव्य एक साथ कई संदेश देता है-

एक, स्वयं भागवत इस वर्ष 11 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे—क्या वे पद त्याग की पहल करेंगे?

दो, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है—यानी ठीक एक हफ्ते बाद वे भी इसी उम्र सीमा में प्रवेश करेंगे।

तीन, संघ और भाजपा के संबंधों में वह आत्मीयता अब नहीं रही, जो कभी सुदर्शन और अटल युग में थी।

इसलिए यह वक्तव्य शायद सिर्फ एक वरिष्ठ प्रचारक की श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य के अगले अध्याय का संकेत है।

संघ और मोदी- दरारें जो अब रेखाएं बन गईं

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा (जनवरी 2024) तक संघ और मोदी के बीच सामंजस्य बना रहा, लेकिन चुनावी मौसम में जब 'मोदी की गारंटी' केंद्रबिंदु बन गई, संघ ने प्रचार से दूरी बना ली। प्रचारक वर्ग से यह स्पष्ट निर्देश था कि 'कार्यकर्ता पार्टी के लिए नहीं, राष्ट्र की विचारधारा के लिए काम करता है, और यदि विचारधारा छूटने लगे तो दूरी बनाना ही विवेक है।'

परिणाम सामने था—भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई।

संघ का स्पष्ट संदेश था—'व्यक्ति नहीं, विचारधारा सर्वोपरि।'

विधानसभा चुनावों में संघ ने फिर से सक्रिय भागीदारी की, विशेषकर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में। लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' के सफल सैन्य अभियान का श्रेय जिस तरह से प्रधानमंत्री ने केंद्रित किया, उसने संघ की नाराज़गी को और गहरा कर दिया। संघ के भीतर यह प्रश्न गूंज रहा है—'क्या यह कार्यकर्ता आधारित संगठन अब व्यक्तिवाद की चपेट में है?'

राजनीतिक उत्तराधिकार और संभावित टकराव

मोहन भागवत का 16 वर्ष का कार्यकाल एक युग रहा है—संघ के भीतर और बाहर दोनों जगह। यदि वे शताब्दी वर्ष से पहले स्वयं पद से निवृत्त होते हैं, तो यह संघ की परंपरा को नई वैधता देगा। लेकिन यदि नरेंद्र मोदी इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं और सत्ता में बने रहते हैं, तो यह संघ-भाजपा संबंधों में सबसे बड़ी वैचारिक दरार बन सकती है। विपक्ष ने इस बयान को लेकर मोदी पर सीधा हमला किया है—'संघ प्रमुख ने अब मोदी को रिटायरमेंट का इशारा दे दिया है।' राजनीतिक टिप्पणीकार नीलांजन मुखोपाध्याय ने कहा, 'अगर मोदी संकेत को नजरअंदाज करते हैं, तो आने वाले महीनों में संघ और भाजपा के बीच टकराव सार्वजनिक रूप ले सकता है।'

भारतीय राजनीति के लिए यह यथार्थ स्वीकार करना कठिन हो सकता है कि एक गैर-राजनीतिक संस्था (RSS) आज भी सत्ताधारी दल की दिशा और नेतृत्व तय करने की क्षमता रखती है। लेकिन यही संघ का स्वभाव है—'छाया में रहकर दिशा देना।' मोहन भागवत का बयान एक ऐसे दौर की शुरुआत हो सकता है जिसमें भाजपा को वैचारिक अनुशासन और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बीच चुनाव करना होगा।

- **क्या मोदी 2026 के बाद सत्ता से दूरी बनाएंगे?**
- **क्या भाजपा में उत्तराधिकार की रूपरेखा संघ के अनुसार बनेगी?**
- **या फिर यह टकराव भाजपा को एक नई स्वतंत्र पहचान देगा—संघ से परे?**

लेकिन संघ के शब्दों में अक्सर इतिहास का संकेत छिपा होता है। और जब वह संकेत 75 की उम्र के इर्द-गिर्द बुना जाए, तो यह केवल अवकाश का नहीं, उत्तराधिकार का अध्याय होता है। वर्ष 2025-26, भाजपा और संघ के रिश्तों की परीक्षा की घड़ी होगा।

चीन नहीं तय करेगा मेरा उत्तराधिकारी : दलाई लामा

धर्मशाला के मैक्लॉडगंज की पहाड़ियों में जब तिब्बती भिक्षुओं का तीन दिवसीय सम्मेलन चल रहा था, तब वहां गूंजे शब्द केवल आस्था के नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सांस्कृतिक स्वाभिमान के थे। 90वें जन्मदिवस की दहलीज़ पर खड़े परम पावन दलाई लामा ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि उनके उत्तराधिकारी का चयन न तो कोई सत्ता करेगा, न कोई सरकार, और न ही चीन की विस्तारवादी लालसा।

दलाई लामा का यह बयान केवल एक धार्मिक घोषणा नहीं, बल्कि उस वैश्विक संघर्ष की पुनरावृत्ति है जो आज आस्था और अधिनायकवाद के बीच लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा- **'मेरा पुनर्जन्म न तो किसी राजनीतिक सत्ता के आदेश पर होगा, और न ही किसी मजबूरी में। अगला दलाई लामा वहां जन्म लेगा जहां स्वतंत्रता सांस लेती हो, जहां परंपरा का सम्मान हो, न कि सत्ताधीशों की मोहर।'**

यह वक्तव्य बीजिंग के सत्ता गलियारों में जैसे विस्फोट बनकर गिरा। चीन ने अपने पुराने राग की पुनरावृत्ति करते हुए 'गोल्डन अर्न' की प्रक्रिया का हवाला दिया- एक प्रक्रिया जो मिंग और किंग वंशों के दौर में उपयोग होती थी, और जिसे अब चीन अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार धार्मिक व्यवस्था पर थोपना चाहता है।

लेकिन विडंबना देखिए, यही चीन उस पान्चेन लामा को दुनिया से गायब कर चुका है, जिसे स्वयं दलाई लामा ने मान्यता दी थी। और अब उसकी जगह अपनी कठपुतली पान्चेन लामा को बैठाकर बौद्ध परंपरा पर शिकंजा कसने का दुस्साहस कर रहा है।

इस बार चीन की चालों के जवाब में भारत चुप नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खुले मंच से स्पष्ट कहा -'दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह निर्णय केवल वे ही ले सकते हैं। इसमें किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।' साथ ही उन्होंने दलाई लामा को 'सिर्फ तिब्बतियों का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का आध्यात्मिक मार्गदर्शक' बताया।

केवल बयान तक सीमित न रहते हुए, भारत सरकार ने अपने प्रतिनिधियों -केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और वरिष्ठ नेता ललन सिंह को दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में भेजकर यह संदेश भी दिया कि भारत इस विषय पर गंभीरता से तिब्बती भावना के साथ खड़ा है।

धर्म के बहाने राजनीति नहीं चलेगी

चीन वर्षों से बौद्ध धर्म को नियंत्रित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पान्चेन लामा की जबरन नियुक्ति और अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर दावा उसी नीतिगत ढांचे का हिस्सा है। चीन की कोशिश है कि तिब्बती संस्कृति को नियंत्रित कर वह न केवल तिब्बत पर राजनीतिक कब्ज़ा बनाए रखे, बल्कि आध्यात्मिक नेतृत्व भी अपनी मुट्ठी में कर ले।

परंतु यह भूलना खतरनाक होगा कि तिब्बती परंपराएं केवल धार्मिक नहीं हैं, वे संपूर्ण जीवन-दर्शन की प्रतिनिधि हैं। पुनर्जन्म का निर्णय किसी आध्यात्मिक संत की आत्मशक्ति और परंपरा के सामंजस्य से जुड़ा है, न कि किसी पार्टी ऑफिस से निकलने वाले आदेश से।

भारत का यह रुख केवल तिब्बत के समर्थन में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उठी एक बुलंद आवाज है। आज जब चीन हांगकांग से लेकर उइगर मुसलमानों तक हर असहमति को कुचलने पर आमादा है, ऐसे में भारत द्वारा दिया गया यह स्पष्ट संदेश न केवल कूटनीतिक है, बल्कि नैतिक भी।

दलाई लामा का यह ऐलान दरअसल यह भी स्पष्ट करता है कि अगला उत्तराधिकारी किसी भी जाति, लिंग या उम्र का हो सकता है- यानी अब परंपरा में समावेश और व्यापकता की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। यह न केवल तिब्बती आस्था के लिए क्रांतिकारी क्षण है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए धार्मिक नेतृत्व के स्वरूप में परिवर्तन का संकेत है।

चीन की नीति स्पष्ट है -'धर्म को सत्ता की जंजीरों में बांधो और आस्था को राजनीतिक औजार बनाओ।' लेकिन दलाई लामा की शांत मुस्कान और उनके दृढ़ विचार इस चाल को हर बार विफल करते आए हैं।

भारत ने जिस साफगोई से चीन के हस्तक्षेप को खारिज किया है, वह केवल एक देश का रुख नहीं, बल्कि एक सिविलाइज़ेशनल स्टैंड है। यह उस भारत की प्रतिध्वनि है जो नालंदा की भूमि से बुद्ध के विचारों को दुनिया को दे चुका है।

दलाई लामा का उत्तराधिकारी कोई भी हो , बच्चा, महिला या कोई साधक - वह उस परंपरा का वाहक होगा जो प्रेम, करुणा और स्वतंत्रता की नींव पर टिकी है। यह भारत और तिब्बत के साझा आत्मिक संबंधों की विजय है और चीन के चेहरे पर लगती एक सभ्य तमाचा।

कागज़ पर हरियाली, ज़मीन पर उजाड़

‘जब जंगल काटे जाते हैं, तब सिर्फ पेड़ नहीं गिरते — गिरता है कानून, संवैधानिक विश्वास और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य।’

रायगढ़, छत्तीसगढ़ — जहां एक तरफ संविधानिक संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही हैं, वहीं सरकारी कंपनियों और प्रशासनिक मशीनरी ने मिलकर कानून की टहनी तोड़ने का अभ्यास शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र पावर जेनरेशन कंपनी ङ्क महाजेनको की, जिसे रायगढ़ जिले के गारे-बालमा सेक्टर-2 में कोयला खदान के लिए वन क्षेत्र आवंटित किया गया है। इस परियोजना से 14 गांव सीधे प्रभावित हो रहे हैं, और विडंबना देखिए — ग्रामसभा से न तो सहमति ली गई, न वन अधिकार अधिनियम का पालन हुआ, न ही पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों को माना गया।

कानून की किताब बंद, कंपनियों की खिड़की खुली

वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) साफ़ कहता है — ‘किसी भी वन भूमि के हस्तांतरण या व्यावसायिक उपयोग से पूर्व, संबंधित ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।’ लेकिन महाजेनको की कोयला परियोजना के लिए 14 गांवों से ना कोई ग्राम सभा की अनुमति ली गई, न ही कोई प्रस्ताव पारित किया गया।

आरटीआई से हुआ खुलासा – न कोई बैठक, न कोई मुहर

पर्यावरण और आरटीआई कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी ने इन सभी ग्राम पंचायतों से ग्राम सभा की बैठक की जानकारी आरटीआई के तहत मांगी। जवाब में — अधिकांश पंचायतों ने लिखित में स्पष्ट किया कि ग्राम सभा हुई ही नहीं। कुछ ने कहा कि खदान का प्रस्ताव आया था, लेकिन ग्राम सभा ने उसका विरोध किया। तो अब सवाल यह है —

- महाजेनको किस ग्राम सभा की अनुमति दिखा रहा है?
- वो दस्तावेज कहां से आए, जिन पर गांव के सरपंच के नाम से नकली हस्ताक्षर थे?
- एनजीटी ने पर्यावरणीय मंजूरी रद्द की, फिर भी पेड़ कटे

15 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने यह स्पष्ट रूप से कहा — ‘महाजेनको को जुलाई 2022 में दी गई पर्यावरणीय मंजूरी गैरकानूनी है और **स्वास्थ्य मूल्यांकन रिपोर्ट के बिना दी गई है।’ आईसीएमआर की रिपोर्ट, जो फरवरी 2020 में ही तैयार हो चुकी थी, उसे झूठे बहाने से अधूरी बताया गया। फिर भी, **सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ हजारों पेड़ दो दिन में काट दिए गए — जैसे जंगल अपराधी हों और प्रशासन जल्लाद।**

‘कोरोना काल में ग्राम सभा?’

मुड़ागांव, जो इस परियोजना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, को FRA के तहत सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त है। यानी यह जंगल गांव की सामूहिक संपत्ति है। क्या यह कल्पना भी की जा सकती है कि — बिना पूछे, कोई बाहरी कंपनी आकर आपके खेत, बगीचे और आंगन को खोद दे, और आप खाली हस्ताक्षर मान लिए जाएं? महाजेनको ने दावा किया कि ग्राम सभा की बैठकें 2020-21 में हुईं। लेकिन तब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी।

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित थीं। तो फिर इन बैठकों की वैधता कहां से आती है?

विरोध पर लाठी, सवाल पर हिरासत

जब 26 जुलाई को गांव वालों ने जंगल कटाई का विरोध किया, तब उन्हें क्या मिला?

पुलिस की घेराबंदी,

स्थानीय प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी,

और दो दिन तक अंधाधुंध पेड़ों की कटाई।

पर्यावरण कार्यकर्ता रिंचिन कहती हैं **‘यह सिर्फ जंगल की कटाई नहीं, संविधान की हत्या है।’**

रायगढ़ बना ‘कार्बन कॉरिडोर’

रायगढ़ पहले से ही अन्य कोल माइंस, थर्मल पावर प्लांट और भारी उद्योगों से घिरा है। अब यहां एक के बाद एक नई खदानें खोली जा रही हैं, जबकि NGT ने 2020 में ही साफ चेतावनी दी थी कि इस क्षेत्र का पर्यावरण नाजुक और संतुलनहीन है। तो अब सवाल ये हैं...

क्या वन अधिकार अधिनियम सिर्फ कागज़ के लिए है? जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं इस पर सुनवाई कर रही हैं, तो ज़मीनी स्तर पर इतनी मनमानी क्यों? अगर FRA, EIA और NGT के आदेशों की अवहेलना इसी तरह होती रही, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मूल्य क्या बचा रहेगा?

क्या अब सच्चाई भी अप्रुवल से निकलेगी?

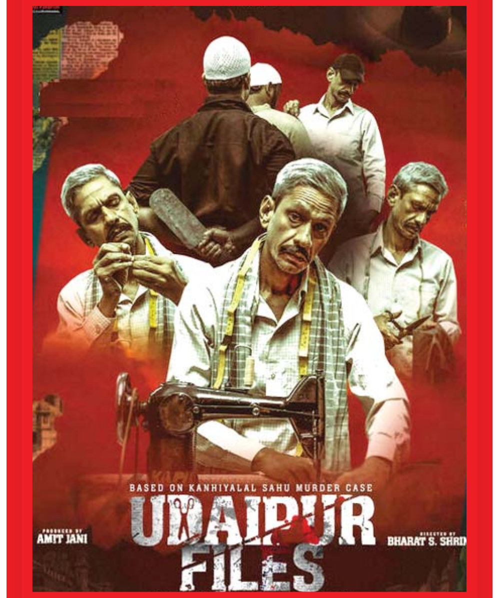

जब कट्टरता गला रेतती है, और न्याय चुप्पी ओढ़ लेता है – तब सवाल पैदा होता है- क्या हम अब भी लोकतंत्र में हैं या ‘डर के लोकतंत्र’ में?

2022 में राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या महज़ एक अपराध नहीं थी, वह इस देश की आत्मा पर एक नुकीला हमला था। एक दर्जी, जो अपने काम में मगन था, जिसने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक फेसबुक पोस्ट की – उसे दुकान के अंदर बेरहमी से गला रेत कर मार दिया गया। और फिर हत्यारों ने वीडियो जारी कर इस ‘कत्ल-ए-इस्लाम’ को ग्लोरीफाई किया।

अब तीन साल बाद, जब ‘उदयपुर फाइल्स’ नाम की एक फिल्म इस नृशंसता को पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है, तो दिल्ली हाईकोर्ट कहता है – ‘रुको, यह फिल्म साम्प्रदायिक तनाव भड़का सकती है।’

यह कैसा न्याय है?

क्या संवेदनशीलता का अर्थ सच्चाई पर पाबंदी है?

जमीअत उलेमा-ए-हिंद कोर्ट पहुंचती है और कहती है कि यह फिल्म ‘सामाजिक सौहार्द’ को नुकसान पहुँचा सकती है। उनके वकील कपिल सिब्बल साहब का कहना है कि फिल्म ‘विवाद’ को जन्म दे सकती है। लेकिन सिब्बल साहब, विवाद किससे? सच्चाई से? या उस सच्चाई को देखने से, जो आपको असहज कर देती है?

अगर एक फिल्म से दंगे भड़कते हैं, तो क्या इसका समाधान फिल्म पर रोक है ङ्क या फिर उस कट्टरता से निपटना, जिसने कन्हैया लाल की हत्या की?

CBFC ने काट-काटकर ‘तथ्यों’ को भी छील डाला

स्वराज्य मैगज़ीन की रिपोर्ट कहती है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 40 से ज़्यादा कट्स लगाए। यानी तथ्यों को पहले एडिट किया गया, फिर भी कोर्ट ने कहा – ‘नहीं, यह काफी नहीं।’ क्या अब सर्टिफिकेशन बोर्ड की भूमिका भी सिर्फ ‘डमी संस्था’ की रह गई है?

जब कोर्ट मौन हो, तो जनता क्या बोले?

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला न सिर्फ फिल्मकारों की अभिव्यक्ति पर अंकुश है, बल्कि देश की उस चेतना पर भी हमला है जो कट्टरता के खिलाफ खड़ी होती है। क्या यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ है, या उस धर्म के नाम पर हुई ‘जिहादी हिंसा’ के खिलाफ है? फर्क है – लेकिन शायद अदालतें भी अब इस फर्क को समझने से कतराती हैं।

कन्हैया का बेटा पूछता है – कब मिलेगा न्याय?

यश, कन्हैया लाल का बेटा, जो तीन साल से इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है, कहता है –‘जब कोई सच्चाई दिखाना चाहता है, तब कोई संगठन कोर्ट चला जाता है और फिल्म पर रोक लगवा देता है।’

और यही भारत की ट्रैजेडी है – हत्यारों को सज़ा नहीं, सच्चाई को ही सज़ा मिलती है।

इस्लामिक जिहाद कोई कल्पना नहीं, ठोस हकीकत है

NIA की जांच बताती है कि हत्यारों के पास मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी 26/11 के संदेश के साथ थी। यानी यह कोई आवेश में उठाया गया कदम नहीं था ङ्क यह एक ठंडे दिमाग से रचा गया इस्लामिक टेरर अटैक था।

क्या इस देश में अब ‘जिहाद’ शब्द बोलना भी गुनाह हो गया है? क्या ‘कट्टरता’ का नाम लेना भी ‘संवेदनशीलता के विरुद्ध’ हो गया है?

‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक - या सच्चाई पर स्टे?

इस देश में ‘द केरला स्टोरी’ रिलीज होती है, लाखों लोग देखते हैं। ‘कश्मीर फाइल्स’ आती है, पब्लिक उसे समर्थन देती है। अब जब ‘उदयपुर फाइल्स’ सच्चाई को फिर से टुकड़ों में जोड़ने की कोशिश करती है – तो सिस्टम की आंखें चुभने लगती हैं। क्यों?

क्या हम एक ऐसे भारत में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ कट्टरता सहन है, लेकिन कट्टरता का पर्दाफाश असहनीय है?

क्या अदालतों को अब ‘असुविधाजनक सत्य’ से डर लगने लगा है?

कपिल सिब्बल और उनकी टीम कहती है कि यह फिल्म देश को बांट सकती है। लेकिन क्या आप इस देश को पहले ही नहीं बाँट चुके जब एक आम नागरिक को ‘शर्मा के समर्थन’ के कारण मारा गया?

कन्हैया लाल की हत्या ‘सामाजिक सौहार्द्र’ का मसला नहीं है ङ्क यह राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है।

और अंत में...

जब अभिव्यक्ति पर बंदिश, न्याय की कुर्सी पर संकोच, और कट्टरता पर मौन ङ्क तीनों एक साथ हो जाएं, तो देश को समझ लेना चाहिए कि सच्चाई अब अदालत के फैसलों से तय नहीं होती, बल्कि उस जन-जागरण से तय होती है जो सड़क पर उतर कर पूछता है –

‘सच बोलने की कीमत क्यों इतनी भारी है?’

कन्हैया लाल की आत्मा आज भी यह सवाल पूछ रही है

‘क्या मेरे गुनहगारों से ज़्यादा खतरनाक वो हैं जो उनकी सजा को रोक रहे हैं?’

और हम सबको इसका जवाब देना ही होगा।

बस्तर से ब्रसेल्स तक माओवादियों का नया प्रोपेगेंडा

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में माओवादियों की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। जहां एक ओर सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति ने जंगलों में माओवादी ढांचे को बुरी तरह तोड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर अब यह हताश हिंसक संगठन अपने पुराने अस्त्र 'प्रचार' को वैश्विक मंचों पर धार देने की कोशिश में जुट गया है। यह युद्ध अब सिर्फ बंदूक और बारूद तक सीमित नहीं है, बल्कि लैपटॉप और लेंस के ज़रिए 'नैरेटिव वॉर' में बदल चुका है।

जंगल में शिकस्त, सोशल मीडिया पर शोर

बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों ने बीते दशक में माओवादियों की जड़ों को उखाड़ फेंका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़े इस युद्ध की गवाही देते हैं — नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर मात्र 18 रह गई है, और हिंसक घटनाएं आधे से भी कम हो चुकी हैं। कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी, ग्रेहाउंड्स जैसी विशेष बलों की तैनाती, सटीक खुफिया इनपुट और आदिवासियों के बीच विश्वास निर्माण ने मिलकर नक्सलियों की जमीन खिसका दी है। लेकिन... जब जमीन खिसकती है, तो झूठ की दीवारें खड़ी की जाती हैं। अब नक्सली यही कर रहे हैं। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और अंतरराष्ट्रीय 'ह्यूमन राइट्स' मंचों पर भारत सरकार और सुरक्षाबलों के खिलाफ एक सुनियोजित प्रचार युद्ध छेड़ दिया गया है।

ICSPWI: प्रोपेगेंडा का नया हब

'International Committee for Supporting People's War in India (ICSPWI)' नामक संगठन अब नक्सलियों का वैश्विक मुखपत्र बन चुका है। यह संगठन न केवल सोशल मीडिया पर भारत को जनजातियों का दमनकारी बताता है, बल्कि गुरिल्ला युद्ध को तेज करने का आह्वान भी करता है।

हालिया पोस्ट में उन्होंने यह दावा किया कि सुरक्षाबलों की कार्रवाई 'आदिवासियों के नरसंहार' के समान है। असल में यह वही रणनीति है जिससे माओवादी खुद को 'जन-रक्षक' के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि उनकी असलियत गाँव जलाने, स्कूल उड़ाने और विकास कार्यों में बाधा डालने की रही है।

शोधकर्ता ऐश्वर्य पुरोहित इसे 'वैधता की लड़ाई' बताते हैं — जहाँ एक आतंकवादी संगठन खुद को 'जनता की आवाज़' के रूप में प्रमोट करता है, ताकि दुनिया की सहानुभूति बटोरी जा सके।

शहीदी सप्ताह और अर्बन नक्सल कनेक्शन

हर साल की तरह इस बार भी 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सली 'शहीदी सप्ताह' मना रहे हैं। पर अब यह केवल जंगल तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता जैसे शहरों में नक्सल समर्थक कार्यकर्ता इसे 'मानवाधिकार सप्ताह' की आड़ में पेश कर रहे हैं। अर्बन नक्सल समूहों का प्रयास यही है — कि जंगल में मर रहे माओवादी को शहरी विश्वविद्यालयों और वैश्विक संस्थानों के मंच से पुनर्जीवित किया जाए। सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह के दौरान नए भर्ती अभियान, स्मारक आयोजन, डिजिटल सेमिनार और ट्विटर ट्रेंड्स की पूरी रणनीति बनाई गई है।

CCOMPOSA: अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की साजिश

माओवादी संगठन अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं। हाल ही में जारी एक बुकलेट में 'Coordination Committee of Maoist Parties and Organisations of South Asia (CCOMPOSA)' को पुनर्गठित करने की बात कही गई है। नेपाल, ग्रीस, फिलीपींस, अफगानिस्तान, और तुर्की जैसे देशों में माओवादी नेटवर्क पहले से सक्रिय हैं। इनका उद्देश्य दक्षिण एशिया में लाल आतंक को पुनर्जीवित करना और यूरोप-अमेरिका में समर्थन जुटाना है।

यह सिर्फ एक प्रचार नहीं — एक कूटनीतिक चुनौती भी है, जो भारत की विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और साइबर नीति — तीनों को एक साथ झकझोरती है।

सरकार की जवाबी रणनीति- बंदूक और ब्रॉडबैंड दोनों मोर्चों पर युद्ध

भारत सरकार ने अब इस प्रचार युद्ध को भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और छत्तीसगढ़ पुलिस ICSPWI और CCOMPOSA की गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। साइबर सेल और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष सशक्त रूप से रखा जाए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा, 'नक्सलवाद को केवल गोली से नहीं, नैरेटिव से भी खत्म करना होगा।'

वास्तव में यह एक तीर-संग्राम नहीं, माइंड-वॉर है।

आदिवासी ही असली पीड़ित हैं, न कि नक्सलियों के 'सहयोगी'

इस पूरे परिदृश्य में सबसे ज्यादा पीड़ित वह आदिवासी समाज है, जिसे नक्सली 'ढाल' बनाकर खुद को वैध ठहराते हैं। स्कूलों में शिक्षक, अस्पतालों में दवाएं, सड़कों पर आवागमन — यह सब तब संभव हुआ जब माओवादियों का असर घटा। पर अब जब यह खत्म हो रहा है, तब उन्हें 'मानवाधिकार' की याद आ रही है?

इंस्टीट्यूट ऑफ सिविलाइज़ेशनल स्टडीज़ एंड रिसर्च के प्रमुख वेद प्रकाश सिंह कहते हैं —'नक्सली अगर आदिवासी हितैषी होते, तो आज बस्तर में विकास की रफ्तार उनकी गोलियों से नहीं थमती।'

प्रचार का जवाब प्रचार से नहीं, प्रमाण से

सरकार को चाहिए कि वह न केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ाए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रयासों को डेटा, रिसर्च और मानवीय पहलुओं के साथ प्रस्तुत करे।

नक्सलियों का यह आखिरी युद्ध हथियारों से नहीं, शब्दों से लड़ा जा रहा है — और इस बार भारत तैयार है।

फॉरेस्ट से फार्मेसी तक
छत्तीसगढ़ की हर्बल क्रांति

'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय उद्यमियों और वनवासियों को केंद्र में रखते हुए लघु वनोपजों के मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

छत्तीसगढ़, जो अब तक खनिज संपदा और जैविक विविधता के लिए जाना जाता रहा है, अब हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों के क्षेत्र में भी एक नई पहचान गढ़ने जा रहा है। दुर्ग जिले के जामगांव (एम) में हाल ही में स्थापित की गई मध्य भारत की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरक मॉडल बनकर उभरी है। यह इकाई आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों के 'फॉरेस्ट टू फार्मेसी' मॉडल को मूर्त रूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय उद्यमियों और वनवासियों को केंद्र में रखते हुए लघु वनोपजों के मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अगुवाई में राज्य ने न केवल वनों से प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य किया है, बल्कि उन्हें आर्थिक उन्नयन और औद्योगिक विकास से भी जोड़ा है।

औषधीय क्रांति की धरती

करीब 27.87 एकड़ में फैली इस केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई में प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये के आयुर्वेदिक औषधीय उत्पादों का उत्पादन एवं प्रसंस्करण किया जाएगा। यह इकाई छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा निर्मित की गई है और इसके संचालन की व्यवस्था PPP (Public-Private Partnership) मॉडल पर आधारित है।

यहां पर आयुर्वेदिक औषधियों के चूर्ण, सिरप, तेल, अवलेह और टैबलेट के रूप में आधुनिक तकनीक से उत्पादन होगा। फार्मास्युटिकल ग्रेड उपकरणों से सुसज्जित यह इकाई पूरी तरह से गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों पर आधारित है।

इसी परियोजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट, जो 6.04 एकड़ में फैली हुई है और जिसकी लागत 23.24 करोड़ रुपए है। इस यूनिट में गिलोय, कालमेघ, बहेड़ा, सफेद मूसली, जंगली हल्दी, गुड़मार, अश्वगंधा, शतावरी जैसी औषधीय वनस्पतियों से उच्च गुणवत्ता का अर्क निकाला जाएगा। यह अर्क आगे आयुर्वेदिक औषधियों और वेलनेस उत्पादों के निर्माण में प्रयोग किया जाएगा।

आदिवासी समुदायों के लिए वरदान

इस प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से 2000 से अधिक स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। आदिवासी और वनवासी समुदाय, जो अब तक वनों में लघु वनोपजों के संग्रहण तक ही सीमित थे, अब इस औद्योगिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। विशेष रूप से महिलाओं को प्राथमिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे कार्यों में रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी।

छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति में वनोपज आधारित उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार वनों पर निर्भर समुदायों को सिर्फ वन-संरक्षण की भूमिका में नहीं देखना चाहती, बल्कि उन्हें विकास और उत्पादकता के केन्द्र में लाना चाहती है।

हरियाली से हरबल क्रांति की ओर

छत्तीसगढ़ का यह कदम केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सामाजिक सशक्तिकरण, और पारंपरिक ज्ञान के आधुनिकीकरण का सामूहिक प्रयास है।

यह प्रयोग आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है ङ्ग जहां जंगल केवल लकड़ी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी औषधियों, रोजगार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनते हैं।

जामगांव से निकली यह हर्बल क्रांति, छत्तीसगढ़ को केवल आयुर्वेदिक नक्शे पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक बदलाव की वैश्विक कथा में भी एक अग्रणी पात्र बना रही है।